20 मई, 2023 ★ वर्ष 32, पृष्ठ संख्या 60, अंक-5

राजस्थान सुजस

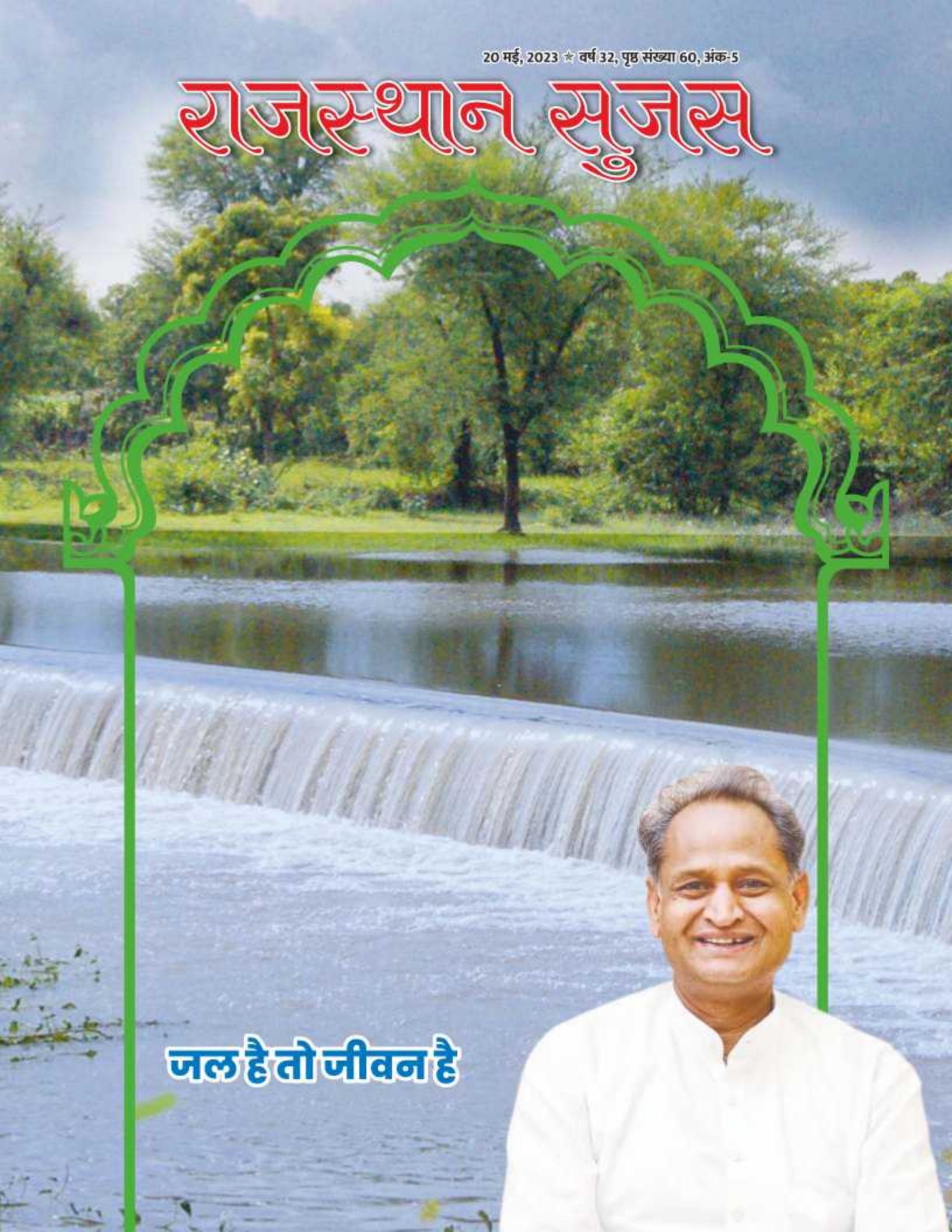

जल है तो जीवन है

जनजातीय संस्कृति में आतिथ्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हर तबके के उत्थान के लिए सतत प्रतिबद्ध हैं और हर मौके पर आमजन के बीच रहकर खुशियां बांटते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन उदयपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी बहुल ब्लॉक कोटड़ा क्षेत्र में मनाया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत घाटा गांव में महंगाई राहत कैंप निरीक्षण के लिए पहुंचे और लाभार्थियों को मिल रही राहत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने एक जनजाति परिवार के बीच अपने जन्मदिन की खुशियां बांटी। घाटा गांव में श्री धमाराम गरासिया की झोपड़ी में पहुंच कर मुख्यमंत्री ने अल्पाहार किया। पलाश के पत्तों से बने दोने में मुख्यमंत्री ने लापसी व पकोड़ों का लुत्फ उठाया। जनजाति परिवार की परंपरागत लोक संस्कृति को देखकर मुख्यमंत्री अभिभूत हुए। आदिवासी युवतियों ने पारंपरिक नृत्य-गीतों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों से मुख्यमंत्री की अगवानी की।

आलेख और छाया: डॉ. कमलेश शर्मा
संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क

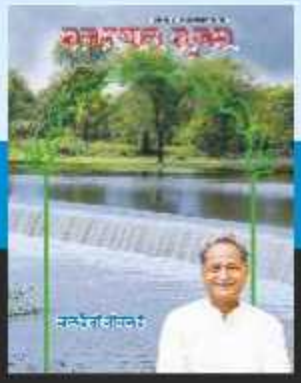

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 32 अंक 05

मई 2023

इस अंक में

लोक जीवन	02
संपादकीय	04
शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम	05
जल जीवन मिशन	09
साक्षात्कार	10
बातचीत	12
जवाई क्लस्टर-4 परियोजना	13
इंदिरा गांधी नहर परियोजना	14
जवाई पुनर्भरण परियोजना	18
बहुमंजिला भवनों की पेयजल नीति	20
बूंद-बूंद सहेजने की पटपटाएं	22
राजस्थान की बावड़ियां	24
खड़ीन	28
झालरा	32
भू-जल बचाने के सनेकित प्रयास	34
पाणी ढूळे, म्हारो जी बळे	36
डिग्गी निर्माण	38
खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार	39
महंगाई राहत कैंप	40
हर वर्ग को मिल रहा संबल	42
राजीव गांधी युवा मित्र	46
जयपुर मेट्रो कला दीर्घा	54
पणिहारी	56
पन्नाधाय, अमराजी अगत पैनोरमा	57
खेल-खिलाड़ी	58
धरोहर	59
तब और अब	60

प्रधान संपादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक
सम्मत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

सहायक संपादक
महेश पारीक

आवरण छाया
सूजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रैनबो ऑफसेट प्रिंटर्स

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 98292-71189, 94136-24352
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।
कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

जल अनमोल है

वेदों में जल को प्राण तत्व मानकर स्तुति की गई है :

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न: ।। (ऋग्वेद,10.9.3)

हे जल के दिव्य प्रवाह! अन्न आदि उत्पन्न कर प्राणीमात्र का पोषण करने वाले जल के देवता (आपो)! हम आपका सान्निध्य चाहते हैं। हमारी अधिकतम वृद्धि हो।

जीवन के उद्भव और विकास का आधार होने की वजह से हमारे यहां पानी को सहेजने की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत जल्द यह अहसास कर लिया था कि जहां तीन से चार महीने ही पानी बरसता है, वहां अगर बरसात के पानी को संचित नहीं किया गया तो सूखे दिनों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों के मुताबिक अनेक तरह की जल प्रबंधन की प्रणालियां विकसित की गईं। सभी प्राचीन सभ्यताओं में भी इस तरह के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान सुजस के इस जल विशेषांक में राजस्थान में प्रचलित जल संग्रहण, संरक्षण, जल प्रबंधन के विविध आयामों और परंपराओं की चर्चा की गई है।

पेयजल, सिंचाई और भू—जल स्तर को बढ़ाने की राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में भी इस अंक में बताया गया है। प्रदेश के 13 जिलों की जीवनदायिनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का कार्य प्रगति पर है। नगरीय क्षेत्रों की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए नीति बनाई गई है।

इस अंक में महंगाई राहत कैंपों की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। 24 अप्रैल से राज्य के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर तक आयोजित महंगाई राहत कैंपों में पात्र लोगों को राज्य सरकार की 10 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों में भी इन कैंपों को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया है।

मई माह का सुजस का यह जल विशेषांक अभिवादन एवं शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत है।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

आमजन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम

राज्य की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं

शिवानी सैनी
सहायक अभियंता (एनआरडब्ल्यू), जन स्वा. अभि. विभाग

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद यहां सतही जल की उपलब्धता देश में उपलब्ध सतही जल की मात्र 1.16 प्रतिशत है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, वर्षा की मात्रा एवं निरंतरता में कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहने से कई ब्लॉक्स के डार्क जोन में आने के बावजूद प्रदेश के हर व्यक्ति को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही पेयजल की गुणवत्ता बरकरार रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हर घर जल पहुंचाने की मुहिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के करीब 63 प्रतिशत गांवों एवं ढाणियों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूजल है। भूगर्भीय जल का सीमित उपयोग एवं सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनाने के साथ ही वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण एवं बारिश के पानी के समुचित संग्रहण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सतही जल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही वर्षा जल को संगृहीत कर भू-जल स्तर में वृद्धि करना राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए चुनौती है।

पेयजल योजनाओं की निरंतरता मुख्यतः भूजल पुनर्भरण पर निर्भर करती है। राज्य सरकार के जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग (वाटरशेड) द्वारा भू-जल पुनर्भरण की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले सात वर्षों में करीब 15 हजार गांवों में 3 लाख जल संग्रहण संबंधी कार्य किए गए हैं। इनमें मुख्यतः एनिकट, चेकडैम, परकुलेशन टैंक, ट्रेंचेस, तालाब, जोहड़, खड़ीन, टांका, फार्म पॉण्ड जैसे कार्य किए जा रहे हैं। कुओं, ट्यूबवैल, हैण्डपंप आदि की मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग करने के बाद इनकी लोकेशन के आसपास वाटर रिचार्ज

स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। इनमें से एक लाख कार्यों से भूजल रिचार्ज में मदद मिली है। प्रदेश के 16 जिलों के परियोजना क्षेत्रों में औसतन 4.66 फीट भूजल रिचार्ज हुआ है। सूखे कुएं और हैण्डपंपों में फिर से पानी आने लगा है। रिचार्ज स्ट्रक्चर के आसपास कोई नया जल स्रोत बनाया जाए तो उसमें पानी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।

पेयजल उपलब्धता के लिए किए जा रहे प्रयास

शहरी पेयजल व्यवस्था - राज्य के सभी 228 शहरों एवं कस्बों को विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। सभी शहर एवं कस्बे पाइप्ड पेयजल योजना से जुड़े हुए हैं। यानी इन्हें नलों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से 120 शहरों को सतही जल स्रोतों से तथा 62 शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 46 शहरों की पेयजल योजनाएं सतही एवं भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित हैं।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था – प्रदेश में कुल 43,362 आबाद गांव तथा 78,254 आबाद ढाणियां हैं। इनमें विभिन्न योजनाओं द्वारा 43,231 गांवों तथा

69,353 ढाणियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभांवित किया जा रहा है। करीब 24,955 गांव एवं 52,210 ढाणियां भूजल से जबकि 18,276 गांव एवं 17,143 ढाणियां सतही जल स्रोतों से लाभांवित हैं। कई स्थानों पर भूजल में फ्लोराइड एवं खारेपन की समस्या को देखते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न तकनीक उपयोग में लाई जा रही हैं। फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए एक्टिवेटेड एल्यूमिना तथा खारेपन को मिटाने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस (आर.ओ.) का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रमुख परियोजनाएं (जल संसाधन विभाग)

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)- ईआरसीपी राज्य की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिससे प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की वर्ष 2051 तक की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन 13 जिलों में प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह परियोजना इन जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

ईआरसीपी के तहत उपलब्ध होने वाले 3,510 मिलियन घन मीटर जल में से करीब 49 प्रतिशत (1,723.5 मिलियन घन मीटर) जल का प्रावधान पेयजल के लिए रखा गया है। फीडर कैनाल के माध्यम से पूर्व में निर्मित क्षेत्र की 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाना प्रस्तावित है ताकि इन बांधों में जल उपलब्धता सुनिश्चित कर पूर्व में सृजित 0.8 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही, परियोजना से करीब 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव होगा। ईआरसीपी से उद्योगों एवं दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के उपयोग के लिए 286.4 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मानसून के दौरान चम्बल बेसिन की सहायक नदी बेसिनों (पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल एवं मेज) में उपलब्ध अधिशेष जल को न्यून जल वाले नदी बेसिनों में अपवर्तित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 19 नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 37,247.12 करोड़ रुपए है।

परियोजना के तहत 6 बैराज एवं एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा।

1. **कुन्नू बैराज** - बारां जिले की शाहबाद तहसील में कुन्नू नदी पर बनेगा जिसकी भराव क्षमता 56.97 मिलियन घन मीटर होगी।
2. **रामगढ़ बैराज** - बारां जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर बनेगा जिसकी भराव क्षमता 50.97 मिलियन घन मीटर होगी।
3. **महलपुर बैराज** - बारां जिले के मांगरौल में बनेगा जिसकी भराव क्षमता 162.20 मिलियन घन मीटर होगी।
4. **नवनेरा बैराज** - कोटा जिले की दिगोद तहसील में कालीसिंध नदी पर बनेगा जिसकी भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर होगी। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा और जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है।
5. **मेज बैराज** - बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर बनेगा जिसकी भराव क्षमता 50.80 मिलियन घन मीटर होगी।
6. **राठौड बैराज** - सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा जिसकी भराव क्षमता 143.09 मिलियन घन मीटर होगी।

इन 5 बैराज के साथ ही सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील में 2,099 मिलियन घन मीटर क्षमता का डूंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। यह ईआरसीपी के तहत जल संग्रहण का मुख्य बांध होगा। इससे माइक्रो इरिगेशन आधारित 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

परियोजना की ग्रेविटी फीडर की लम्बाई 965 किलोमीटर, टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर, पंपिंग मैन की लंबाई 141 किलोमीटर एवं नेचुरल स्ट्रीम की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। इसके तहत 15 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में परियोजना को शीघ्र धरातल पर लाने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ईआरसीपी कॉर्पोरेशन) गठित करने की घोषणा की थी। 17 जून 2022 को निगम के गठन के आदेश जारी किए गए थे। ईआरसीपी के दो महत्वपूर्ण घटकों – नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नर्मदा नहर परियोजना – परियोजना में 1,793 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं एवं उप-वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परियोजना में 2,231 डिग्गियों का निर्माण कर 1,215 डिग्गियों पर पंपिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। इस पर अभी तक 3,242.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

परवन वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना – यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के लोगों को पेयजल, सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत इन तीनों जिलों के 1,821 गांवों में पेयजल तथा 637 गांवों के 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत 490 मिलियन घन मीटर क्षमता का एक बांध बनाया जा रहा है। इसमें 317 मिलियन घन मीटर जल सिंचाई के लिए आरक्षित है। 50 मिलियन घन मीटर जल पेयजल, 16 मिलियन घन मीटर जल शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य तथा 79 मिलियन घन मीटर जल तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आरक्षित है। पहले चरण में 1 लाख 31 हजार 400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में 70 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना – इस परियोजना के तहत चम्बल नदी से 6.54 क्यूमैक्स पानी प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च तक लिफ्ट कर धौलपुर तहसील के 65 गांवों, मनिया तहसील के 83 गांवों, राजाखेड़ा तहसील के 83 तथा सैंपऊ के 25 गांवों यानी कुल 256 गांवों के 39 हजार 980 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। परियोजना में पेयजल के लिए 10 प्रतिशत पानी आरक्षित है।

ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना – ईसरदा बांध बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनैठा तहसील उनियारा, टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इससे दौसा जिले के 1,079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव एवं एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। परियोजना से कुल 19 लाख की आबादी को सतही पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। इसमें बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में मांगली डूंगरी नदी एवं गणेश नाला पर निर्माणाधीन गरड़दा सिंचाई परियोजना, झालावाड़ जिले के गांव कालापीपल में आहू नदी पर निर्माणाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना (कोटा), बारां जिले के खजूरिया गांव में ल्हासी नदी पर ल्हासी सिंचाई परियोजना तथा बारां जिले के करवरी खुर्द गांव में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं में सिंचाई एवं पेयजल दोनों के लिए जल आरक्षित किया गया है।

> पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) राज्य की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिससे प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की वर्ष 2051 तक की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन 13 जिलों में प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह परियोजना इन जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

लघु सिंचाई परियोजनाएं – कम समय एवं कम लागत में सिंचाई सुविधा के विस्तार में ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश में कुल 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत थीं।

बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना कार्य – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में 18 बड़े बांधों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण को शामिल किया गया। इनमें बीसलपुर, जवाई, सूकली, सेलवाड़ा, माही, गम्भीरी, मातृकुण्डिया एवं सोम-कमला-अम्बा, पांचना, रामपुर, पार्वती, छापरवाड़ा, जाखम, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज शामिल हैं। 2021-22 के बजट में भी 18 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए शामिल किया गया। इनमें जग्गर, सीलिबेरी, सैंथल सागर, बाड़ी मानसरोवर, चिनार, सादड़ी, कादम्बरी, कैर, बांकली, भीमलत, बारेठा, नंदसमंद, भंवरसैमला, मोरा सागर, सुरवानिया, वागन, गोवता एवं मैजा शामिल हैं।

प्रमुख परियोजनाएं (जलदाय विभाग)

चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना – 3 हजार 106 करोड़ रूपये की इस परियोजना से धौलपुर जिले के 132, भरतपुर के 953 गांवों एवं भरतपुर के 8 शहरों (भरतपुर, रूपवास, उच्चैन, कुम्हेर, डीग, नगर, कामां एवं सीकरी) की वर्ष 2054 तक की लक्षित 37 लाख 88 हजार की आबादी पेयजल से

लाभांवित होगी। परियोजना के माध्यम से धौलपुर एवं भरतपुर जिले के 743 गांवों में 1 लाख 61 हजार जल कनेक्शन (एफएचटीसी) होंगे।

परवन-अकावद पेयजल परियोजना – 3 हजार 523 करोड़ रुपये की इस वृहद परियोजना से कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के 1,402 गांवों एवं 276 ढाणियों में पेयजल पहुंचेगा।

राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना (तृतीय चरण) – 1,799 करोड़ रुपये की इस परियोजना से जोधपुर शहर के साथ ही 2,167 गांवों की वर्ष 2054 तक की आबादी की पेयजल मांग की पूर्ति होगी। इसमें जोधपुर जिले के 1,830, बाड़मेर के 211 एवं पाली के 126 गांव शामिल हैं। परियोजना में 213 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन मदासर गांव के पास प्रस्तावित एस्केप रिजर्वायर से जोधपुर तक बिछाई जा रही है। चार उच्च क्षमता के पंप हाउस भी बनाए जा रहे हैं।

जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र के 524 गांवों में हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए 1062.77 करोड़ रुपये की इस पेयजल परियोजना से 2053 तक की अभिकल्पित 76 लाख की आबादी को पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। इस परियोजना के माध्यम से 82 हजार 525 जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

1 हजार 661 करोड़ रुपये की नवनेरा बैराज से कोटा, बूंदी एवं बारां की पेयजल परियोजना

हिण्डौली-नैनवा परियोजना - 973.84 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 286 गांवों को पेयजल सुविधा मिलेगी। 82 हजार से अधिक एफएचटीसी होंगे।

बीसलपुर-पृथ्वीराजनगर पेयजल परियोजना स्टेज प्रथम (फेज-प्रथम)- जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र एवं झोटवाड़ा के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के निवासियों की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए बीसलपुर बांध आधारित योजना से पानी उपलब्ध कराने हेतु 563.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रथम चरण में दी गई। योजना में वर्ष 2051 तक की अभिकल्पित 14 लाख 95 हजार से अधिक आबादी को करीब 284 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन तथा 30 वर्ग किमी क्षेत्र में वितरण लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा 19 उच्च जलाशय, 9 स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस तथा कुल एक हजार किलोमीटर से अधिक की ट्रांसमिशन/ राइजिंग मेन एवं वितरण लाइनें बिछाने के कार्य होंगे।

13 हजार 328 करोड़ रुपये की परियोजनाएं होंगी पूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कई बजट घोषणाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी हो जाएंगी और इनका लाभ आमजन को मिलेगा। इनमें पिछले बजट की घोषणाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार मार्च, 2024 तक 13 हजार 328 करोड़ रुपये की विभिन्न पेयजल परियोजनाएं पूरी होंगी।

698.72 करोड़ रुपये की नोखा-बीकानेर पेयजल परियोजना इस वर्ष मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से नोखा एवं बीकानेर पंचायत समिति के 137 गांव तथा कोलायत क्षेत्र के 9 गांवों की जनता लाभांवित होगी।

330 करोड़ 92 लाख रुपये की जोधपुर जिले की देवनिया-नाथरू पेयजल परियोजना तथा 459 करोड़ रुपये की बीकानेर जिले की खाजूवाला जलप्रदाय योजना के कार्य मार्च, 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य है।

254 करोड़ रुपये की बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-ए (बाड़मेर-बायतू-बालोतरा) एवं पार्ट-डी (भणियाणा, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर) परियोजना तथा 231 करोड़ रुपये की इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर-झुंझुनूं, सीकर, खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

175 करोड़ रुपये की अजमेर जिले की ब्यावर- जवाजा पेयजल परियोजना, 133.48 करोड़ रुपये की राजसमंद जिले की बाघेरी का नाका क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तथा 159 करोड़ रुपये की नागौर जिले की जायल मातासुख पेयजल परियोजना इसी वर्ष पूरी हो जाएंगी। 198.80 करोड़ रुपये की चूरू जिले की आपणी योजना-द्वितीय चरण (रतनगढ़-सुजानगढ़ सेक्शन) अप्रैल 2023 में तथा 104 करोड़ 49 लाख रुपये की डूंगरपुर जिले की सोम-कमला-अंबा बांध से आसपुर की पेयजल परियोजना के कार्य भी सितम्बर 2023 तक पूरे करने का लक्ष्य है।

151 करोड़ रुपये की छापी-झालावाड़- झालरापाटन पेयजल परियोजना का कार्य सितम्बर, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 130 करोड़ रुपये की बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया बांध से बागीदौरा, बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक की पेयजल परियोजना का कार्य जून, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 169 करोड़ 51 लाख रुपये की कोटा जिले की रामगंजमंडी-पचपहाड़ पेयजल परियोजना का कार्य सितम्बर, 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में शामिल 1,274.26 करोड़ रुपये की इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजर्वायर निर्माण की परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डिपोजिट कार्य के रूप में 4 एस्केप रिजर्वायर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें 300 करोड़ रुपये लागत से आरडी-750 पर एस्केप रिजर्वायर, 242.31 करोड़ रुपये लागत से आरडी-1356 पर एस्केप रिजर्वायर निर्माण, 311.62 करोड़ रुपये की लागत से आरडी-1121 पर एस्केप रिजर्वायर तथा 232.95 करोड़ रुपये की लागत से आरडी-507 पर एस्केप रिजर्वायर निर्माण के कार्य चल रहे हैं। •

तेजी से ऊपर चढ़ा जल जीवन मिशन का ग्राफ

प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान शीर्ष राज्यों में

अविचल चतुर्वेदी, एमडी (जल जीवन मिशन), पीएचईडी

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

हर घर में नल के माध्यम पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। योजना के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिसंबर, 2019 में जारी किए गए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के आधार पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है।

जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय राजस्थान में महज 10 प्रतिशत जल कनेक्शन ही पहले से उपलब्ध थे जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम थे। दिसंबर, 2019 में प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी जो अब बढ़कर 40.68 लाख हो गई है। इस प्रकार 2019 से लेकर अब तक प्रदेश में 29 लाख नए जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जेजेएम में अब तक 14 हजार 992 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उच्च स्तर पर निरंतर की जा रही मॉनिटरिंग एवं समीक्षा से प्रदेश में मिशन का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है।

जल जीवन मिशन ने जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में रफ्तार पकड़ी और तीन महीनों में 7 लाख 34 हजार 715 जल कनेक्शन दिए गए। जनवरी से मार्च की तिमाही के प्रतिदिन जल कनेक्शन को देखें तो राजस्थान, देश में तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान में 31 मार्च 2023 को एक दिन में ही 27 हजार 470 जल कनेक्शन किए गये। इससे पहले 26 मार्च 2023 को 16,742 जल कनेक्शन किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 14 लाख 13 हजार 679 जल कनेक्शन किए जा चुके हैं। मार्च, 2023 में 3 लाख 74 हजार 65 ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए।

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं छितराई हुई बसावट के कारण जन सेवाओं की प्रदायगी में अत्यधिक राशि व्यय करनी पडती है एवं समय भी अधिक लगता है। इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में 90 प्रतिशत जल संबंधों (Connections) की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। वर्तमान में 87.65 लाख जल संबंधों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। करीब 52 लाख (60 प्रतिशत) जल संबंधों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। 9.36 लाख जल संबंधों के कार्यादेश जून माह में तथा 22.32 लाख जल संबंधों के लिए कार्यादेश जुलाई, 2023 तक जारी किए जाएंगे। 1.42 लाख जल संबंध अन्य योजनाओं जैसे डीएमएफटी एवं जायका में स्वीकृत किए गए हैं।

जल स्रोतों के अभाव, छितराई बसावट एवं अत्यधिक लागत के कारण करीब 1.57 लाख जल संबंध नॉन-फिजिबल की कैटेगरी में हैं। राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखकर मिशन की अवधि मार्च, 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। घर पर ही नल से जल मिलने लगेगा तो हमारी बहन-बेटियों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इससे उनके समय की बचत होगी और वे पढ़-लिख कर आगे बढ़ेंगी।

जेजेएम के तहत प्रदेश के कुल 43 हजार 364 गांवों में से 43,251 गांवों में ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है। करीब 13 हजार ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का बैंक खाता खोला जा चुका है। इन समितियों के गठन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान जेजेएम के तहत विलेज एक्शन प्लान तैयार करने में भी देश में सबसे आगे है। अभी तक 43 हजार 208 ग्राम कार्य योजनाएं (Village Action Plan) बनाई जा चुकी हैं जो कि देश में सर्वाधिक हैं। ग्राम सभाओं के माध्यम से इनका अनुमोदन कराया जा रहा है। राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए जेजेएम के तहत घरेलू जल संबंध महिला मुखिया के नाम से ही जारी करने का प्रावधान किया है। इन्हीं प्रयासों की वजह से ही मार्च 2023 में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान, देश में दूसरे स्थान पर रहा। •

पेयजल आपूर्ति
की प्रदेश में सुचारु व्यवस्था

गर्मी के मौसम को देखते हुए समर कंटींजेंसी के तहत सभी जिला कलेक्टर्स को 50-50 लाख रुपये आकस्मिक कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक 33 जिलों में 16 करोड़ 23 लाख रुपये के 319 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में आमजन को राहत प्रदान की जा सके।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी से
मुस्तफा शेख, सहायक निदेशक जनसंपर्क द्वारा किये गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश।

प्रदेश में सुचारु पेयजल आपूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है। पेयजल गुणवत्ता बरकरार रखते हुए राज्य के सभी 228 शहरों/कस्बों को विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं से तथा 43,231 गांवों एवं 69,353 ढाणियों को ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है।

गर्मी के मौसम को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

गर्मी के मौसम को देखते हुए समर कंटींजेंसी के तहत सभी जिला कलक्टर्स को 50-50 लाख रुपये आकस्मिक कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक 33 जिलों में 16 करोड़ 23 लाख रुपये के 319 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में आमजन को राहत प्रदान की जा सके।

ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल माह से अगस्त, 2023 तक 172 शहरों/कस्बों में जल परिवहन के लिए 39.76 करोड़ तथा 22,689 गांवों में जल परिवहन के लिए 82.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है। अभी पेयजल की कमी वाले प्रदेश के 34 शहरों/कस्बों - जयपुर, अजमेर, डीडवाना, बांदीकुई, महुवा, दौसा, बसवा, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, बगरू, अंता, बूंदी, कोटा, करौली, तिजारा, अलवर, राजगढ, खेड़ली, तारानगर, रतनगढ़, राजलदेसर, विदासर, सुजानगढ़, डीग, बारी, हिण्डौन, फलौदी, बालोतरा एवं सिवाना में 2,886 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया जा रहा है।

राज्य के 18 जिलों - अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बारां, बूंदी एवं कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,199 गांव-ढाणियों में 1,426 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन पेयजल परिवहन किया जा रहा है, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी दिनों में बढ़ाया जाएगा। जिलों में टैंकरों से जल परिवहन व्यवस्था एवं दरों के निर्धारण के लिए जिला कलक्टर एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई हैं। टैंकरों की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस एवं ओटीपी की व्यवस्था की गई है।

पेयजल की समस्या वाले गांवों, कस्बों एवं आबादियों में 3,249 नए ट्यूबवैल तथा 5,322 हैंडपम्प कमीशन किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक 29 हजार 800 हैण्डपंपों की मरम्मत की गई है। पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए चीफ इंजीनियर एवं एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। जलदाय विभाग के सभी क्षेत्रीय एवं जिलों के प्रभारी अभियंताओं को हैंडपम्प मरम्मत अभियान, पेयजल योजनाओं के रखरखाव तथा मॉनिटरिंग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को पेयजल से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो।

आमजन की पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय टोल फ्री नम्बर 181 के अलावा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन में राजस्थान की प्रगति कैसी है?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में जल जीवन मिशन अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उच्च स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा से प्रदेश में मिशन का ग्राफ काफी ऊपर चढ़ा है। अभी तक प्रदेश में 40.68 लाख

कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान ने अब तक के सर्वाधिक जल कनेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 31 मार्च को एक दिन में 27 हजार 470 कनेक्शन किए हैं। इससे पहले 26 मार्च को 16,742 जल कनेक्शन किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 14 लाख 13 हजार 679 जल कनेक्शन किए जा चुके हैं।

जल का महत्त्व हमारी माताओं-बहनों से अधिक कौन समझ सकता है। जल जीवन मिशन को सफल बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। जेजेएम ने महिलाओं का जीवन आसान किया है। घर के सारे काम-काज छोड़कर एक घड़ा पीने के पानी की जुगत में दूर-दूर तक जाने वाली बहनों को अब घर पर ही नल से जल मिलने लगा है। दूर से पानी भरकर लाने में लगने वाले समय का सदुपयोग अब हमारी बेटियां पढ़ाई में कर आगे बढ़ रही हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए प्रदेश में जेजेएम के तहत घरेलू जल सम्बन्ध महिला मुखिया के नाम से ही जारी करने का प्रावधान किया गया है।

ईआरसीपी पर राज्य में क्या कार्य हो रहे हैं?

प्रदेश के 13 जिलों की जीवनदायिनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है। फिलहाल 1 हजार 284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध के कार्य प्रगतिरत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लेने का प्रावधान किया गया है।

अमृत 2.0 के तहत शहरों में पेयजल से संबंधित क्या कार्य हो रहे हैं?

अमृत 2.0 में शहरी निकायों में स्थित सभी घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना लक्षित है। वर्ष 2025 तक राज्य के प्रत्येक शहरी परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के 178 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लिए अमृत 2.0 के 4,769.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा 2,815.83 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार का 1,666.26 करोड़ रुपये जबकि राज्य सरकार के हिस्से की कुल राशि का 10 प्रतिशत यानी 287.75 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा होगा। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र की हिस्सा राशि 50 प्रतिशत, 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 33.33 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 25 प्रतिशत है। शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अमृत-2 के तहत वर्ष 2025-26 तक 7 लाख 71 हजार 141 नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले से मौजूद 21 लाख 37 हजार नल कनेक्शनों को सुधारा जाएगा।

योजना में 33 लाख 15 हजार 165 आबादी को लाभांवित करने का प्रस्ताव है। इस योजना में 2 लाख 55 हजार 760 शहरी घरों एवं 35 हजार 665 कच्ची बस्तियों में चौबीस घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में कम से कम दो हजार परिवारों को चौबीस घंटे जलापूर्ति का लाभ मिलेगा।

बहुमंजिला इमारतों को पेयजल उपलब्ध कराने के आपके प्रयास कितने सार्थक हुए हैं?

बहुमंजिला भवनों में पीएचईडी द्वारा पेयजल कनेक्शन दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण इन भवनों के रहवासी लम्बे समय से पेयजल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की थी।

इस संबंध में नीति बनाने के लिए मुख्य अभियंता (शहरी) की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अन्य राज्यों में बहुमंजिला इमारतों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनाई गई नीतियों का अध्ययन किया। मल्टी स्टोरी एवं निजी टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। विस्तृत अध्ययन एवं सभी के सुझावों को समाहित करते हुए बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन की नीति तैयार की गई।

राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी।

रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/अन्य संस्था/समिति अथवा विकासकर्ता द्वारा आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल सम्बन्ध हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को चैक करने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आवासीय बहुमंजिला इमारतों को कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी।

जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए आपका क्या संदेश है?

पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए वैज्ञानिक वहां की मिट्टी में जलीय अंश खोजते हैं क्योंकि इसके बिना वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। जल की बचत ही जल का उत्पादन है, 'जल है तो कल है', 'जल ही जीवन है' ये सभी साधारण स्लोगन नहीं बल्कि सारगर्भित कथन हैं। इन्हें आमजन तक पहुंचाकर उन्हें भविष्य के लिए पानी बचाने की मुहिम में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। किसी भी कार्य की सफलता के लिए जन भागीदारी जरूरी है।

स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण एवं पानी के बेहतर प्रबंधन के बारे में चैप्टर शामिल किए जाने चाहिए ताकि कम उम्र से ही बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

पानी की कीमत और उसका बेहतर प्रबंधन जैसलमेर एवं बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों से अधिक कोई नहीं जान सकता। वहां बूंद-बूंद पानी को सहेजकर कम से कम पानी में गुजारा करना बचपन से ही सिखाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को समय रहते पानी का महत्व समझना होगा। •

अंतिम छोर के उपभोक्ता तक

पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

अति. मुख्य सचिव, पीएचईडी एवं जल संसाधन डॉ. सुबोध अग्रवाल से
मुस्तफा शेख, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) पीएचईडी एवं जल संसाधन विभाग की बातचीत

राजस्थान में भूजल की वर्तमान स्थिति कैसी है और जल संरक्षण की दिशा में किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है?

विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता 2,000 घनमीटर है, देश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1,700 घनमीटर जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता मात्र 640 घनमीटर है। हमारे यहां पशुधन की अधिकता के कारण पेयजल की मांग भी निर्धारित मापदण्डों से अधिक रहती है। प्रदेश की 71 प्रतिशत जल योजनाएं पूर्णतः भूजल पर आधारित हैं जबकि करीब 75 प्रतिशत ब्लॉक्स में भू-जल की स्थिति अत्यंत गंभीर है। प्रदेश के बड़े भू-भाग में उपलब्ध भूजल पीने योग्य नहीं है। पूरे देश की गुणवत्ता प्रभावित गांव-ढाणियों में से 34 प्रतिशत राजस्थान में हैं। पेयजल योजनाओं के लिए स्रोतों की दीर्घकालीन सस्टेनेबिलिटी प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

राज्य बजट 2023-24 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ी क्या घोषणाएं की गई हैं?

राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 3 हजार 133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराने के लिए 11 हजार 255 करोड़ रुपये की 3 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें 5 हजार 776 करोड़ रुपये की चम्बल-अलवर-भरतपुर पेयजल परियोजना, 4 हजार 657 करोड़ रुपये की चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती परियोजना तथा 822 करोड़ रुपये की चम्बल नदी आधारित कालीतीर परियोजना शामिल हैं।

अवैध जल कनेक्शन एवं बूस्टर्स के खिलाफ अभियान में क्या प्रगति है?

गर्मी के दिनों में अंतिम छोर तक के उपभोक्ता तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अवैध कनेक्शन हटाने एवं अवैध बूस्टर्स के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इस वर्ष अप्रैल माह से लेकर अभी तक 2,900 अवैध जल संबंध हटाए गए तथा 332 कनेक्शन नियमित किए गए। इस अवधि में 524 बूस्टर्स भी जब्त किए गए हैं। पिछले साल गर्मी के मौसम में 868 बूस्टर्स जब्त किए गए थे। शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पाइपलाइन चिह्नित कर बदली जा रही हैं। वितरण लाइन से अवैध कनेक्शन कर पेयजल चोरी के प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। हैण्डपंप मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिए 2,500 संविदा श्रमिकों एवं 560 किराए के वाहनों के लिए स्वीकृति दी गई है। नहरबंदी से प्रभावित 10 जिलों के 49 शहरों एवं 8,294 गांवों के करीब एक करोड़ 80 लाख लोगों के लिए पेयजल प्रबंधन किया जा रहा है।

डेनमार्क यात्रा के दौरान आपने क्या देखा, वहां की तकनीक यहां कैसे काम आ सकती है?

डेनमार्क में पेयजल वितरण में मीटरिंग सिस्टम काफी प्रभावी है एवं पानी के उपयोग के विरुद्ध राजस्व वसूली तकरीबन 100 प्रतिशत है। वहां पानी का लीकेज 5 प्रतिशत से कम है। डेनमार्क में भूजल दोहन के साथ ही भूजल को रिचार्ज करने पर भी ध्यान दिया जाता है। वहां लागू की गई तकनीक अपनाकर हम पेयजल वितरण में विभिन्न कारणों से होने वाले लीकेज को कम कर सकते हैं। डेनमार्क के अनुभवों से सीखते हुए राजस्थान में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं।

डेनमार्क में संसाधनों के सेल्फ सस्टेनेबल (आत्मनिर्भर) होने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वहां के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एनर्जी न्यूट्रल होते हैं, उसका पर्यावरण पर भी विपरीत असर नहीं पड़ता। डेनमार्क में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली इस स्लज को उपयोग में लेते हुए इसमें से फोस्फॉरस आधारित खाद बनाई जा रही है एवं इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा रहा है।

डेनमार्क के वाटर सेक्टर में काम कर रहे विश्वविद्यालयों द्वारा भूजल की उपलब्धता और स्थिति मापने के लिए तकनीक विकसित की गई है। इससे एरियल सर्वे एवं जमीनी सर्वे द्वारा भूजल की स्थिति का वास्तविक आकलन किया जा सकता है। यह तकनीक राजस्थान में भूजल की स्थिति मापने में काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। वहां पेयजल प्रबंधन का फ्रेमवर्क तैयार करने, शहरी जल, स्मार्ट वॉटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ऊर्जा उत्पादन तथा नदियों के पुनरुद्धार जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर कार्य किया जा रहा है। •

जवाई क्लस्टर-4 परियोजना

224 गांवों का शुद्ध पेयजल आपूर्ति का सपना पूरा

सम्पत राम चांदोलिया
उपनिदेशक, जनसंपर्क

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई से लगभग संपूर्ण पाली जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को परियोजना से नहीं जुड़े होने के कारण पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने जवाई बांध क्लस्टर-4 परियोजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय के फलस्वरूप जवाई क्लस्टर-4 परियोजना का काम शुरू हुआ।

बाली, सुमेरपुर एवं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के क्रमशः 134, 11 एवं 79 गांव सहित कुल 224 गांवों एवं 121 ढाणियों को जवाई से लाभान्वित करने हेतु परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना को वित्त विभाग से 476 करोड़ का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हुआ।

परियोजना में बाली तहसील के 78 गांव, देसूरी तहसील के 78 गांव एवं रानी तहसील के 68 गांव सम्मिलित हैं। परियोजना से वर्तमान लक्षित कुल 3.07 लाख आबादी तथा वर्ष 2047 तक 5.17 लाख आबादी लाभान्वित होगी। योजना के तहत एक रॉ वाटर जलाशय, 10 स्वच्छ जलाशय, 11 पम्पिंग स्टेशन, 805 कि.मी. पम्पिंग मेन एवं 874 कि.मी. वितरण पाइपलाइन आदि कार्य करवाए गये है। 10 स्वच्छ जलाशय क्रमशः जवाई, दांतीवाड़ा, बीजापुर, नाडोल, नारलाई, डायलाना, सालरिया और नाणा, बेड़ा, मुंडारा में कार्य किया जा चुका है। 67 उच्च जलाशय एवं 51 भू-तल जलाशय का कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में 224 गावों में से 175 गावों में नियमित जल आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

34 एमएलडी क्षमता युक्त फिल्टर प्लांट निर्माण

जवाई क्लस्टर-4 परियोजना के तहत बांध से पेयजल की आपूर्ति से पूर्व पानी की साफ—सफाई के लिए 34 एमएलडी प्रतिदिन क्षमता वाले फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया। फिल्टर प्लांट के द्वारा साफ व गुणवत्तायुक्त पानी क्षेत्रवासियों को मिल सकेगा।

67 उच्च व 51 भूतल जलाशयों का निर्माण

परियोजना के अंतर्गत 67 उच्च जलाशयों व 51 भूतल जलाशयों का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी का संग्रहण किया जा सकता है।

1664 किलोमीटर पाइपलाइन

जवाई बांध से 224 नए गांवों मे पेयजल आपूर्ति के लिए 1,664 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया।

10 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण

परियोजना के तहत 10 पम्पिंग स्टेशन बनाए गए। ये पम्पिंग स्टेशन पेयजल को 200 किलोमीटर की रेंज में आपूर्ति करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। •

पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

नहर सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। यह मरुभूमि को हिमालय के मीठे पानी से सिंचित करने के साथ करोड़ों राजस्थानियों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। इस नहर का उद्गम पंजाब स्थित हरिके बैराज से है। यहां से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर (170 कि.मी. पंजाब, हरियाणा और 34 कि.मी. राजस्थान) निकली है। राजस्थान में यह नगर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर आरंभ होती है। यह श्रीगंगानगर, बीकानेर जिले से निकलती हुई जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना के लिए रावी-ब्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 एमएएफ पानी का प्रावधान निर्धारित है।

हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दो चरणों में विभाजित किया गया है। हरिके बैराज से बीकानेर जिले के पूगल तक के 393 कि.मी क्षेत्र को प्रथम चरण कहा जाता है। इस चरण के समस्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इसके अधिकांश भाग के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रगतिरत है। इस चरण में मुख्य नहर की लंबाई 256 किलोमीटर है, जो पूगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है।

इस परियोजना से लाभांवित क्षेत्र के शहरों, गांवों, कस्बों और मंडियों में रोजगार के अवसर व आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई है। बुनियादी सुविधाओं के विकास से यहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। इस परियोजना में गैर सिंचाई परियोजनार्थ 1,200 क्यूसेक पानी आरक्षित है। इससे पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं और सीकर जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है अथवा करवाया जाना है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना को भी इस नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पश्चिमी राजस्थान में ताप, सौर, गैस बिजली घरों द्वारा विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों के विकास में इस नहर प्रणाली से मिलने वाले पानी का योगदान है। सूरतगढ़, रामगढ़, गिरल, गुढ़ा, बरसिंहसर तथा राजवेस्ट की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाड़मेर की निर्माणाधीन रिफाइनरी को भी इसी नहर से पानी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। कुल मिलाकर यह नहर दस जिलों के करोड़ों लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है।

राज्य सरकार के मौजूदा कार्यकाल में नहर सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां

- वर्ष 2018-19 में काश्तकारों को 6 बारियों, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 9 बारियों में पानी उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2021-22 में पानी की सीमित

उपलब्धता होने पर भी काश्तकारों को 5 बारियों तथा वर्ष 2022-23 में काश्तकारों को 9 बारियों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया गया।

- इंदिरा गांधी नहर द्वितीय चरण की नहरें लगभग पचास वर्ष पुरानी हैं। इन नहरों की मरम्मत एवं नवीनीकरण आवश्यक है। इसके लिए लगभग 2,160 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना की क्रियान्विति विभिन्न चरणों में की जानी है।
- नाबार्ड की RIDF-XXV योजना के तहत आईजीएनपी के स्टेज-II में बीकानेर जोन के दंतौर, नाचना, अवाई, साकड़िया वितरिका प्रणाली एवं सीधी निकलने वाली माइनरों के नवीनीकरण एवं आधुनीकीरण की कुल प्रस्तावित लागत 121 करोड़ है। इसमें से 79.66 करोड़ रुपये का ऋण नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। अप्रैल 2023 तक इसके विरुद्ध 79.53 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्तमान में 4 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 2 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके तहत दंतौर, नाचना, अवाई, साकड़िया आदि के 97,616 हेक्टेयर सिचिंत क्षेत्र में कुल 480 कि.मी. लंबी नहरों की मरम्मत एवं सृदृढ़ीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। इससें बीकानेर, खाजूवाला, कोलायत, बज्जू, पूगल एवं पोकरण तहसील के लगभग 25 हजार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- RIDF-XXV। खाजूवाला-बीकानेर की थोथा, भूट्टों वाली वितरिका एवं बरसलपुर शाखा का 135 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए अप्रैल 2023 तक 49.25 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट नहरों के 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा CADWM योजना के तहत वर्ष 2016 में 1,658.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इससे चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट एवं करणी सिंह लिफ्ट के 1.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 865 डिग्गियों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपये हैं। अप्रैल तक इन पर 408.42 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा संख्या 141.03 में लिफ्ट योजनाओं साहवा, गजनेर, कोलायत में शेष रही लगभग 400 डिग्गियों का निर्माण 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाने की घोषणा की थी। इसके तहत 439.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के पश्चात 282.85 करोड़ रुपये के कार्यों (269 डिग्गियों के लिए) के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल, 2023 तक इन पर 33.43 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या 141.04 वर्ष 2022-23 के तहत बीकानेर के बीछवाल जलाशय को पेयजल आपूर्ति करने वाली कंवरसेन लिफ्ट नहर के जीर्णोद्धार के लिए 215.41 करोड़ के 57 कार्यों के कार्यादेश दिए गए। अप्रैल 2023 तक 13.90 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। इन 57 में से 53 कार्य अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं।

विभाग के अभिनव प्रयोग एवं नवाचार

- वर्षा अथवा अन्य कारणों से इंदिरा गांधी मुख्य नहर में क्षमता से अधिक मात्रा में आए अतिरिक्त जल को पूर्व में एस्केप के माध्यम से व्यर्थ छोड़ दिया जाता था। इस पानी का उपयोग पेयजल के लिए करने के उद्देश्य से नहर के नजदीक स्थित प्राकृतिक गड्ढों (Natural Depressions) को पक्का किया गया है। इन्हें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की घर-घर नल स्कीम को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराये जाने के निर्णय के तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर की RD-507, RD-750, RD-1121 तथा RD-1356 पर 1274 करोड़ की लागत से एस्केप जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त पश्चिमी राजस्थान के गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सके। इसमें से RD-507 व RD-750 के रिजर्वायर का निर्माण बीकानेर में करवाया जा रहा है। इन कार्यों पर अप्रैल, 2023 तक क्रमशः 12.81 करोड़ एवं 15 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। ये कार्य मार्च, 2024 तक पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं।

विभाग की उपलब्धियां

- इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तेजपुरा माइनर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित कर जल उपयोग क्षमता (दक्षता) बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के तहत वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।
- नहरों में स्काडा आधारित जल मापन व मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापना सहित नहरों के प्रभावी रखरखाव व संचालन से एकीकृत बहुआयामी सिंचित क्षेत्र विकास के लिए फरवरी, 2020 में सीबीआईपी अवॉर्ड, 2020 प्राप्त किया। •

ईआरसीपी : एक वरदान

डॉ. महेश सरधना
स्वतंत्र लेखक

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह संपूर्ण देश के लगभग 10.41 फीसदी भू-भाग पर विस्तृत है और संपूर्ण देश की लगभग 6 प्रतिशत जनसंख्या यहां निवास करती है। राजस्थान अपने गौरवमयी इतिहास, परंपराओं और रचनात्मक संस्कृति के लिए विश्वभर में जाना जाता है। यहां के लगभग 61 फीसदी भू-भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। इस वजह से इसे मरुप्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। इस वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहां तरह—तरह के 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि के उत्पादन एवं बागवानी में भी राज्य के किसानों ने नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन एक बड़े भू-भाग पर मरुस्थल का विस्तार होने एवं बारहमासी नदियों का अभाव के साथ-साथ एक बड़ा क्षेत्र अल्प वर्षा वाला होने के कारण राज्य में जल की कमी रहती है।

राज्य का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जल की कमी का सर्वाधिक सामना करता है। यह क्षेत्र सघन वनस्पति विहीन भी है। पानी की कमी का प्रभाव एवं जल का महत्व यहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी देखने को मिलता है। लोकगीतों में जल बचाने का संदेश मिलता है। यहां के आम जीवन में जल संरक्षण की विधियां अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। शेष राजस्थान में भी समय-समय पर वर्षा की कमी और अनिश्चितता तथा अकाल व सूखे की वजह से यहां के निवासियों के जीवन के साथ-साथ पशुपालन पर भी बुरा असर पड़ा है। ऐसी स्थितियों ने जीवन जीने की परिस्थितियों को विकट बना दिया है। वर्ष 2000 के अकाल एवं 2009 के सूखे की परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं हैं।

राज्य में नहरों का विस्तार

इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार जालोर और बाड़मेर जिले तक है। इसी पर सरदार सरोवर बांध, सतलुज नदी पर गंग नहर, पश्चिमी यमुना पर भरतपुर नहर, यमुना नदी पर यमुना (गुड़गांव) नहर, माही नदी पर भीखाभाई सागवाड़ा नहर और बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना राज्य की प्रमुख बड़ी नहर परियोजनाएं हैं।

प्रमुख लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नारायण सागर बांध (अजमेर), जय सागर बांध (अलवर), वैथली, ल्हासी, अंधेरी, परवन-विलास (बारां), बटाडू का कुआं (बाड़मेर), बंद बरेठा (भरतपुर), चाकन, मेज कनकसागर, गरदड़ा (बूंदी), बड़गांव वागन, औराई, गंभीरी (चित्तौड़गढ़), ताल छापर (चूरू), चिरिमीरी, रेहडियां सागर, सिलिमिली, माधवसागर (दौसा), तालाबशाही, पार्वती (धौलपुर), सोम—कमला—अंबा, गैप सागर (डूंगरपुर), बांकली बांध (जालोर), कानोता बांध, छापरवाड़ा बांध (जयपुर), चोली, पीपलाद, गागरिन, कालीसिंध, छापी, भीमसागर, हरिश्चंद्र (झालावाड़), अजीत सागर (झुंझुनूं), जसवंत सागर बांध, बालसमंद, उम्मेद सागर बांध (जोधपुर), गोपालपुरा, तकली, अलनिया, हरिश्चंद्र सावनभाटी (कोटा), जवाई सागर (पाली), नंद समंद (राजसमंद), ईसरदा, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई, पिपलोदा, मोरेल (सवाई माधोपुर), सुकली, सेलवाड़ा (सिरोही), जानासागर, सोम कागदर, मानसी वाकल परियोजना (उदयपुर), मेजा बांध (भीलवाड़ा), एवं पांचना बांध (करौली) शामिल हैं।

एक तरफ जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना के प्रयासों से राज्य का उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से संपन्न हो रहा है, वहीं राज्य के पूर्वी भाग में इस तरह की कोई बड़ी नहर परियोजना नहीं होने के कारण और धीरे-धीरे भूमिगत जल का स्तर नीचे जाने से पूर्वी राजस्थान में पेयजल व सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस वजह से इस बड़े भू-भाग एवं यहां पर निवास करने वाली राज्य की तकरीबन 40 फीसदी आबादी के लिए एक प्रमुख सिंचाई एवं पेयजल परियोजना की आवश्यकता समझी गई।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) राज्य की एक बड़ी एवं महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है जिससे मानसून के दौरान चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों जैसे कुन्नू कूल, पार्वती, मैज आदि में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल बांध, गंगा पार्वती, कालीसिंध, गंभीरी में अपवर्तित किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत अधिशेष पानी का अपवर्तन किया जाएगा। इस

ईआरसीपी के लिए सर्वदलीय बैठक

परियोजना के अंतर्गत राज्य के पूर्वी भाग के लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि सिंचाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा। साथ ही पेयजल प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना का विस्तार राज्य के 13 जिलों में होगा जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर,अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले सम्मिलित हैं। इन्हें 2051 तक की पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जानी है। इसके साथ ही पूर्व में निर्मित 26 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भी जल प्राप्ति होगी। इनमें चाकन (बूंदी) ठीकरिया कुम्हारिया गलवा, गलवानिया, मासी, टोरडी सागर, बीसलपुर (टोंक), कालीसिंध, पांचना, जग्गर (करौली), जयसमंद (अलवर), पार्वती, राम सागर, तालाब शाही, उर्मिला सागर (धौलपुर), रामगढ़, कालख, कानोता, छापरवाड़ा (जयपुर), बंद बरेठा भरतपुर आदि में जल डालकर लगभग 0.80 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 2 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विकास किया आएगा। इसके अतिरिक्त डीएमआईसी के निर्माण तथा औद्योगिक इकाइयों में उपयोग के लिए 286.4 एमटी जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के चहुंमुखी विकास का आधार बनने की पूर्ण रूप से संभावनाएं लिए हुए है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के अंतर्गत बांधों का निर्माण कम किया जाएगा और बैराज अधिक बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 बैराज प्रस्तावित हैं। बांध निर्माण करने से एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है जिसके अंतर्गत बांध के कैचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य जनजीवन के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विकसित आर्थिक क्रियाएं और गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज प्रस्तावित हैं। कुन्नू 56.97, रामगढ़ 50.49, महलपुर 162.20 (बारां), नवनेरा (कोटा) 226, मेज (बूंदी) 50.80, राठौर बैराज 143.09 (सवाई माधोपुर) औरडूंगरी बांध बनास नदी पर तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर में प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर तंत्र की कुल लंबाई 1,268 किलोमीटर प्रस्तावित है जिसकी ग्रेविटी फीडर के अंतर्गत लंबाई 965 किलोमीटर, पंपिंग मैन की लंबाई 141 किलोमीटर, नेचुरल स्ट्रीम की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 15 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

परियोजना की मौजूदा स्थिति

इस परियोजना का प्रारूप 2005 में संपादित मध्य प्रदेश — राजस्थान अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक के अनुरूप ही है, इसलिए यह सुखद है कि अब इस परियोजना पर मध्य प्रदेश की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से लगातार बैठकें एवं पत्र व्यवहार कर रहे हैं और इस परियोजना की भविष्य में आवश्यकता बताते हुए केंद्र सरकार से इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके दो महत्वपूर्ण घटक नवनैरा बैराज एवं ईसरदा बांध का कार्य प्रारंभ कर दिया है और इनकी आधारभूत संरचना विकसित कर दी गई है। वर्तमान सरकार का यह भगीरथी प्रयास आने वाले समय में मरुभूमि के पूर्वी भाग को जल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर समृद्ध बनाने में सहायक होगा जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और राज्य में आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। •

जवाई पुनर्भरण परियोजना

लक्ष्मण पारंगी
स्वतंत्र पत्रकार

जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है। जवाई बांध का निर्माण वर्ष 1957 में जवाई नदी पर प्रमुख सिंचाई परियोजना के रूप में किया गया था। यह बांध 3,8671 हेक्टेयर क्षेत्र (CCA) की सिंचाई के लिए बनाया गया था। बाद में पाली और सिरोही में पीने के पानी की कमी के कारण हर साल संगृहीत पानी का कुछ हिस्सा पीने के लिए आरक्षित कर दिया जाता था। जवाई बांध (लूनी बेसिन) की सकल क्षमता 7,327.50 एमसीएफटी (207.49 एमसीएम) है। वर्ष 2002-03 से 2022-23 तक इसकी डिजाइन की गई सकल क्षमता 7,327.50 एमसीएफटी के मुकाबले औसत संगृहीत सकल क्षमता 4,255.85 एमसीएफटी है। यहां से जल की लगातार मांग की वजह से इसका जलस्तर बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से दो परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का जवाई बांध में अपवर्तन

क्षेत्र की पेयजल की मांग में लगातार वृद्धि के कारण साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को जवाई बांध में अपवर्तन की परियोजना की परिकल्पना की गई, ताकि मौजूदा जवाई बांध में पानी का अपवर्तन कर पाली और सिरोही जिलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

परियोजना के प्रथम चरण के संबंध में पाली एवं सिरोही जिले की पेयजल की भारी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 मे पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई एवं साबरमती नदी पर जलाशयों का निर्माण करवाने की घोषणा की गई एवं इन जलाशयों से पापलाइन के माध्यम से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

इसमें कार्य को दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में सेई एवं साबरमती नदी पर दो बांध एवं साबरमती नदी पर बन रहे बांध से जवाई बांध जल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय चरण में वाकल नदी में बांध एवं इस बांध से साबरमती नदी पर बन रहे बांध की परिवहन प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है।

साबरमती नदी पर बन रहे बांध से जल सेई नदी पर बन रहे बांध तक टनल ए (5.82 किमी, 5 मीटर व्यास) के माध्यम से जाएगा। सेई नदी पर बन रहे बांध से पंप हाउस तक टनल बी (7.42 किमी, व्यास 5 मीटर) के माध्यम से जाएगा। टनल बी (सेई नदी पर बनने जा रहे बांध से पंप हाउस तक) से संगृहीत पानी पंप हाउस में प्रवेश करेगा। फिर इसे 43.5 मीटर के टोटल स्टैटिक हेड से 384 मीटर के रिड्यूस्ड लेवल तक पंप किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 2 मीटर व्यास के माइल्ड स्टील से बने तीन राइजिंग मेन का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद संगृहीत पानी 3 मीटर व्यास के माइल्ड स्टील से बनी 15.12 किलोमीटर लंबी प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से आगे जाएगा। फिर स्टोर किया हुआ पानी आउटफॉल टैंक के जरिए ग्रेविटी पाइपलाइन में आएगा। 3.6 मीटर व्यास के प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप से बनी 28.99 किलोमीटर लंबाई की 2 ग्रेविटी पाइपलाइन होंगी जिससे यह जल टनल सी में जाएगा। इसके बाद यह 7.82 किलोमीटर लंबी सुरंग सी में प्रवेश करेगा, जिसमें 5 मीटर का भीतरी व्यास होगा। फिर इसके बाद 3.6 मीटर व्यास के प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप से बनी 5.67 किलोमीटर लंबी ग्रेविटी पाइपलाइन में प्रवेश करेगा। ग्रेविटी पाइपलाइन (बी) से संगृहीत पानी को जवाई नदी के माध्यम से जवाई बांध तक पहुंचाया जाएगा।

कार्य से होने वाले लाभ

परियोजना के पूर्ण होने पर पाली जिले के 9 कस्बे (पाली, रोहत, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसूरी, सोजत, रायपुर, मारवाड जंक्शन) और 560 गांवों को पानी

मिलेगा। इसके साथ ही सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के अंतर्गत शिवगंज कस्बा एवं 178 गांवों की पेयजल सुविधा सुदृढ़ हो सकेगी।

इसके अलावा इससे गुजरात में जा रहे साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का लूणी बेसिन में अपवर्तन किया जाएगा। इससे राजस्थान राज्य के पाली एवं सिरोही जिले की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए सुरंग की क्षमता बढ़ाने का कार्य

जवाई बांध में स्वयं के कैचमेंट से पानी की कमी के दृष्टिगत सन् 1969-78 के मध्य ग्राम तेजा का वास, तहसील-कोटड़ा, जिला उदयपुर में पिंडवाड़ा-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से 1 किलोमीटर की दूरी पर सेई बांध का निर्माण करवाया गया। मूलतः यह एक अपवर्तन परियोजना है जिसका मूल उददेश्य इस बांध में संगृहीत पानी को 6.776 किमी लंबाई की टनल के माध्यम से जवाई बांध में अपवर्तित करना है। वर्ष 2006-08 में सेई बांध की क्षमता बढ़ाने का कार्य किया गया, जिससे सेई बांध की पूर्ण भराव क्षमता 1,106.58 मीटर घन फीट से बढ़ाकर 1,618.97 मीटर घन फीट कर दी गई। बांध का गेज 8.25 मीटर से बढ़ाकर 10.93 मीटर किया गया। सेई बांध का गेज 10.93 मीटर होने से टनल की डिस्चार्ज कैपेसिटी 29.12 मीटर घन फीट से बढ़कर 34.13 मीटर घन फीट प्रतिदिन हो गई। अधिशेष पानी का उपयोग करने हेतु सुरंग की क्षमता में वृद्वि के लिए वैज्ञानिक एवं भूगर्भीय विश्लेषण करवाया गया। एक्सपर्ट रिपोर्ट के अनुसार टनल को 1.5 मीटर गहरी करना सबसे उचित पाया गया।

परियोजना की जरूरत

जवाई बांध से पाली जिले के 33 गांवो के 25,825 हेक्टेयर व जालोर जिले के 24 गांवो के 12,846 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व पाली जिले के 563 गांवो, 9 कस्बों तथा सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में जवाई बांध में पानी की औसत आवक इसकी कुल भराव क्षमता 7,327.50 मीटर घन फीट के विरुद्ध हर वर्ष मात्र 3,800 मीटर घन फीट रही है जो केवल 52 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि पेयजल हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता होने पर रेल द्वारा पानी का परिवहन करना पड़ता है। वर्ष 2019 में ग्रीष्मकाल में पाली शहर के पेयजल हेतु 45 दिन के कंटीजेंसी प्लान में ट्रेन द्वारा पानी के परिवहन पर लगभग 14 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था। परिवहन हेतु ट्रेन के फेरे शुरू कर दिए गए थे। पाली व सिरोही जिलों को प्रतिवर्ष पेयजल के लिए विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। विगत 30 वर्षों में सेई बांध से औसतन 2,163 मीटर घन फीट पानी सेई टनल के माध्यम से अपवर्तित किया जा रहा है। सेई बांध की भराव क्षमता एवं ऊंचाई बढ़ने के उपरांत भी जवाई बांध खाली रह जाता है। जबकि विगत 31 वर्षों में सेई बांध 15 बार ओवरफ्लो हुआ है।

परियोजना से होने वाले लाभ

कार्य पूर्ण होने पर सुंरग की साइज 90 वर्ग फीट से बढ़कर 150 वर्ग फीट हो जाएगी। इसके साथ ही टनल के इनलेट की रिमॉडलिंग का कार्य एवं डीप सबमर्जेंस से इनलेट तक 720 मीटर लंबाई में आरसीसी बॉक्स बैरल का निर्माण करवाया जाएगा। इससे टनल के अंदर जमा होने वाली सिल्ट की मात्रा मे कमी आएगी। सेई बांध के डेड स्टोरेज से अतिरिक्त पानी जवाई बांध में अपवर्तित किया जाएगा। उक्त परियोजना पूर्ण होने पर टनल की क्षमता 34.13 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़कर 73.87 मिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगी एवं जवाई बांध में पहुंचने वाले पानी की मात्रा में औसतन न्यूनतम 840 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिवर्ष की वृद्वि होगी। यानी वर्तमान पेयजल मांग पर चार महीने का अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस कार्य के संपादन से पाली जालोर एवं सिरोही जिले के गांवों एवं शहरों को पेयजल की मांग पूरी होगी। पेयजल हेतु कंटीनजेंसी में प्रतिवर्ष खर्च हो रहे करोड़ों रुपयों की बचत होगी। कम मानसूनी बरसात वाले वर्षों में भी पर्याप्त मात्रा में पेयजल हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, पाली एवं जालोर जिलों की 38,671 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि हेतु उपलब्ध जल की मात्रा भी बढ़ेगी। इस प्रस्तावित परियोजना में प्राकृतिक बहाव से पानी डाइवर्ट करने पर आवर्ती लागत (Recurring Cost) शून्य रहेगी। •

बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जारी की नीति

के. डी. गुप्ता
मुख्य अभियंता (शहरी), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति की अधिसूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की थी।

असल में बहुमंजिला इमारतों एवं निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में जारी परिपत्रों में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से लंबे समय से इन इमारतों में रहने वाले लोगों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। नई नीति की खासियत यह है कि यह पूरे प्रदेश के शहरों में स्थित बहुमंजिला इमारतों के लिए बनेगी जबकि इससे पहले 2016 और 2020 में जारी किए गए परिपत्र सिर्फ जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों को पेयजल कनेक्शन देने को ध्यान में रखकर जारी किए गए थे।

बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन हेतु नीति के मुख्य बिंदु

- आर.डब्ल्यू.ए. (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन)/अन्य संस्था/समिति/विकासकर्ता द्वारा आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल संबंध हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें भवन में निर्मित समस्त इकाइयों की श्रेणी (वाणज्यिक/आवासीय) तथा कारपेट एरिया दर्शित हो।
- बहुमंजिला भवन की श्रेणी में वे भवन आएंगे जिनकी ऊंचाई भवन के कुर्सी स्तर से एवं भवन में भू-तल स्टिल्ट अथवा पोडियम पर होने की स्थिति में स्टिल्ट फ्लोर की छत/पोडियम स्तर से 15 मीटर से अधिक हो।
- बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1,500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1,500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी।
- एकमुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी।
- पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलदाय विभाग द्वारा तैयार कराए जाने वाले बुनियादी ढांचे की हिस्सा राशि एकमुश्त शुल्क के रूप में ली जाएगी। बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध के लिए एकमुश्त शुल्क की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि आर.डब्ल्यू.ए./अन्य संस्था/समिति/ विकासकर्ता द्वारा पेयजल संबंध जारी करते समय जमा कराई जाएगी।
- एकमुश्त शुल्क राशि का शेष 75 प्रतिशत जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किस्तों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगा।
- उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त शुल्क की राशि एक साथ जमा कराने पर कुल एकमुश्त राशि पर 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- बहुमंजिला भवन में पेयजल संबंध आर.डब्ल्यू.ए./अन्य संस्था/समिति/विकासकर्ता को पेयजल उपयोग हेतु घरेलू एवं अघरेलू पेयजल मांग की गणना अनुसार पृथक-पृथक एकल बल्क पेयजल संबंध (Bulk Connection) भू-तल पर जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी इकाई/फ्लैट के मालिक को अलग से पेयजल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

- बहुमंजिला भवन का कुल कारपेट एरिया राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (R E R A) / नगर निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार अथवा इनके द्वारा अन्य अधिकृत सक्षम प्राधिकारी/नगरीय विकास विभाग अथवा स्वायत्त शासन विभाग से पंजीकृत पैनल वास्तुविद् द्वारा बहुमंजिला भवन के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित सभी फ्लैटस/इकाइयों के कारपेट एरिया का कुल योग (Cumulative Sum) होगा।
- बहुमंजिला भवनों हेतु एकमुश्त शुल्क की दरें निम्नानुसार देय होंगी:
- आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- मिश्रित बहुमंजिला भवन में आवासीय क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपये प्रति वर्ग फुट तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- संस्थागत अथवा औद्योगिक बहुमंजिला भवनों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हिस्सा राशि विभागीय बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत की पूर्ण राशि देय होगी।

बहुमंजिला भवन में पेयजल कनेक्शन हेतु देय एकमुश्त शुल्क राशि में छूट

- बहुमंजिला भवन में रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) कार्यात्मक होने पर एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- बहुमंजिला भवन में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली कार्यात्मक होने तथा बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 10 प्रतिशत जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किये जाने की स्थिति में एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- बहुमंजिला भवन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली कार्यात्मक होने तथा बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 20 प्रतिशत जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किये जाने की स्थिति में एकमुश्त शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग को विशेष तौर पर लाभान्वित करने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना में निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट्स) में पेयजल कनेक्शन हेतु विभागीय बुनियादी ढांचे की हिस्सा राशि के रूप में देय एकमुश्त शुल्क की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- उपरोक्त छूट मिलने के बाद इस श्रेणी हेतु देय एक मुश्त शुल्क में से 25 प्रतिशत राशि परियोजना विकासकर्ता द्वारा पेयजल कनेक्शन से पूर्व जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि इस श्रेणी के आवासीय भवन धारकों द्वारा मासिक जल शुल्क के साथ 60 समान किस्तों में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगी।
- उक्त श्रेणी के अंतर्गत ऐसे आवासीय भवन (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.) जिन्हें विकासकर्ता द्वारा निर्मित कर समस्त आवासीय इकाइयां क्रेतागण को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं, उन पर देय एक मुश्त शुल्क की 25 प्रतिशत राशि विकासकर्ता के स्थान पर आर.डब्ल्यू.ए. (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/अन्य संस्था/समिति) द्वारा भी जमा कराई जा सकती है।
- बहुमंजिला भवनों हेतु जल शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसे कि स्थायी शुल्क/सम्बन्ध शुल्क/मीटर शुल्क इत्यादि प्रचलित टैरिफ की सम्बन्धित श्रेणी के अनुसार ही देय होगा।
- बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध जारी करने की वरीयता
- पहली वरीयता : ऐसे क्षेत्र जहां बहुमंजिला भवनों की पेयजल मांग की पूर्ति हेतु स्त्रोत तथा बुनियादी ढांचा दोनों पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।
- दूसरी वरीयता : ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुमंजिला भवनों की मांग की पूर्ति हेतु स्रोत पर्याप्त हैं, लेकिन स्थापित वितरण तंत्र में संवर्धन की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में एकमुश्त शुल्क का न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को तात्कालिक राहत के लिए विभाग द्वारा फिजीबिलिटी के आधार पर एक कनेक्शन दिया जा सकेगा।
- तीसरी वरीयता : ऐसे क्षेत्रों में जहां स्रोत पर्याप्त हैं, परन्तु वितरण तंत्र में संवर्धन की आवश्यकता है।
- चौथी वरीयता : ऐसे क्षेत्रों में जहां स्रोत पर्याप्त हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे में वितरण तंत्र के साथ साथ भण्डारण क्षमता/ट्रांसमिशन मेन लाइन के संवर्धन कार्य भी आवश्यक है।
- पांचवीं वरीयता : ऐसे क्षेत्रों में जहां स्रोत अपर्याप्त हैं तथा स्रोत का संवर्धन भी आवश्यक है।

कनेक्शन के समय आवासीय बहुमंजिला भवनों को पहली, वाणिज्यिक बहुमंजिला भवनों को दूसरी तथा संस्थानिक अथवा औद्योगिक बहुमंजिला भवनों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

बहुमंजिला भवनों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये जल का उपयोग केवल घरेलू पेयजल आवश्यकताओं हेतु किया जाएगा। पेयजल का उपयोग अन्य कार्यों यथा वाहनों को धोने के लिए/विनिर्माण गतिविधियों के लिए/सड़कों व मार्गों को साफ करने के लिए/भवन निर्माण/स्वीमिंग पूल/उद्यान इत्यादि हेतु नहीं किया जा सकेगा।

इससे पहले बहुमंजिला भवनों में पीएचईडी द्वारा पेयजल कनेक्शन दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण इन भवनों के रहवासी लंबे समय से पेयजल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। •

बूंद-बूंद सहेजने की परंपराएं

आलोक आनंद
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

राजस्थान अपनी विषम प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। पेयजल की उपलब्धता यहां भौगोलिक कारकों की वजह से हमेशा ही कम रही, लेकिन इस मरु प्रदेश में रहने वाले लोगों ने अपने जल प्रबंधन कौशल से सदियों से इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। पानी की बूंद-बूंद को सहेजना और उसका सदुपयोग करना राजस्थान वासियों की दिनचर्या का हिस्सा है। अपने जल प्रबंधन के कौशल को राजस्थान के लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में बने विभिन्न जल संरक्षण ढांचे इस बात की गवाही देते हैं कि राजस्थान में जल संरक्षण परंपरा कितनी प्राचीन है।

तालाब और सरोवर निर्माण

भीलवाड़ा के गंगापुर के निकट नांदसा गांव में एक यूप स्तंभ मिला है, जो विक्रम संवत 282 में लिखा गया शिलालेख है। तीसरी सदी के शिलालेख में पुष्करराज तीर्थ का उल्लेख मिलता है। झालावाड़ संग्रहालय में रखे गंगाधर शिलालेख में बावड़ी के निर्माण का उल्लेख किया गया है। यह शिलालेख विक्रम संवत 480 में लिखा गया था। ये शिलालेख बताते हैं कि राजस्थान में बावड़ी और सरोवर निर्माण की परंपरा सदियों पुरानी है।

राजस्थान की प्रारंभिक बावड़ियों में अंबलेश्वर की शुंगकालीन बावड़ी महत्वपूर्ण है। पत्थर से बनी यह बावड़ी आकार में गोल है। इसके नजदीक ही समकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा एक स्तंभ मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में ज्यादातर बावड़ियां वर्गाकार मिलती हैं, जो समय के साथ बावड़ी निर्माण की कला के बदलने और बेहतर होने की ओर इंगित करती हैं।

राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियां

वैसे तो पूरे राजस्थान में बावड़ियां पाई जाती हैं, लेकिन अपने अद्वितीय स्थापत्य और निर्माण की वजह से कुछ बावड़ियां विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं, जिन्हें देखने दुनियाभर से लोग आते हैं। इनमें आभानेरी की चांद बावड़ी का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा। बांदीकुई से 8 किलोमीटर दूर आभानेरी मंदिरों के समूह के साथ ही अपनी बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी एक वैष्णव मंदिर से संबद्ध है जिसे हर्षत माता मंदिर के नाम से जाना जाता हैं। बावड़ी में देव प्रतिमाएं एवं देव कुलिकाएं गढ़ी गई थीं जो इसके सौंदर्य को बढ़ाती है। इस बावड़ी से जुड़ा प्रासाद है जिसमें कक्ष बने हुए हैं। बावड़ी को आठवीं शताब्दी में निर्मित माना जा सकता है।

इसी तरह की एक दूसरी प्रसिद्ध बावड़ी भांडारेज की बावड़ी भी का स्थापत्य अनूठा है। दौसा से 11 किलोमीटर दूर स्थित भांडारेज गांव में बनी इस बावड़ी को बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पांच मंजिल की इस बावड़ी की सीढ़ियां तल तक जाती हैं। सीढ़ियों को छायादार बनाने के लिए उनके ऊपर बरामदे बनाए

हुए हैं। प्रवेश द्वार भी आकर्षक एवं भव्य हैं। यहां एक शिलालेख है जिससे यह पता चलता है कि इस बावड़ी का निर्माण संवत 1789 में कुंभाणी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह ने करवाया था। इसी से थोड़ी दूर नानगरामजी का कुंड है जिसे छोटी बावड़ी कहते हैं। यहां मिले शिलालेख के अनुसार संवत 1891 में राव रणजीत सिंह थूला ने यहां स्थित ब्रज गोपालजी के मंदिर और ठाकुर आनंद सिंह के पुत्र मानसिंह ने छोटी बावड़ी का निर्माण करवाया था।

इसी क्रम में बूंदी की कलात्मक रानी जी की बावड़ी का उल्लेख करना भी आवश्यक है। यह बावड़ी करीब 300 फीट लंबी एवं 40 फीट चौड़ी है। बावड़ी की गहराई 200 फीट के आस-पास है। यहां बना तोरण द्वार भव्य है जो 8 स्थानों पर बना हुआ है। इसकी महराबे 30 मीटर तक ऊंची हैं। बावड़ी में दशावतार एवं नव ग्रहों की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। यहां सरस्वती एवं गणेश की प्रतिमाएं भी मिलती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की परंपरा

सार्वजनिक जलाशयों के निर्माण के साथ ही राजस्थान में घरेलू जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण की परंपरा भी रही है। घरों में कुंडी, कुंड, टांका और छोटे तालाब बनाकर उनमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। घरों में बनने वाले कुंडी व टांके के निर्माण के लिए जमीन के भीतर बड़ा सा कुंड बनाकर उसमें प्रकाश एवं हवा की व्यवस्था करते हुए एक चबूतरा बनाकर ढंक दिया जाता था। इन चबूतरों को रामरज, खड़िया और गेरू से बने रंगों से आकृतियां या रंगोली बनाकर सजाया जाता था। कुंडे छोटे और टांके बड़े होते हैं। राजस्थान में तो कई टांके इतने विशाल होते हैं कि बड़ी आबादी इनसे वर्ष भर पानी पीती है। जयपुर के जयगढ़ किले में बना टांका इतना विशाल है कि उसमें 60 लाख गैलन पानी समा सकता है। इस टांके के 81 खंभे हैं। जल संग्रहण के लिए राजस्थान में खड़ीन निर्माण की परंपरा भी रही है। खड़ीन अस्थाई तालाब होते हैं। ये दो तरफ से मिट्टी और तीसरी तरफ से पत्थर की दीवार की मदद से बनाए जाते हैं। इन्हें कहीं-कहीं पाल का धोरा भी कहा जाता है। खड़ीन जानवरों के पानी पीने और सिंचाई के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं की भी प्राचीन परंपरा है। इस मरु प्रदेश में भूमिगत जल

बहुत गहराई में मिलता है। इस वजह से यहां के कुएं भी काफी गहरे होते हैं। यहां पाए जाने वाले साठी कुएं 300 फीट तक गहरे होते हैं। जोधपुर जिले के फलौदी जिले में सेठ सांगीदास का साठी कुआं अपनी अनुपम वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी के हर गांव में सैंकड़ों साल पुराने कुएं मिलते हैं, जिनके साथ ऊंची मिनारें बनाने की परंपरा रही है। बीकानेर में बने चौतीना कुएं को अनूप सागर भी कहा जाता है। बीकानेर के प्रमुख कुओं में बख्ता सागर, कोठारियों का कुआं, चंदन व रतन सागर, रघुनाथ सागर, राणीसर और फूल कुआं शामिल हैं।

राजस्थान में पानी सहजने के साथ ही उसके उपयोग को लेकर भी बहुत सावधानी बरती जाती है। बाड़मेर और जैसलमेर में नहाने के दौरान एक पात्र में बैठकर नहाया जाता है ताकि स्नान के दौरान उपयोग हुए पानी को घर की साफ-सफाई और पौधों को सींचने में दोबारा उपयोग में लिया जा सके। राजस्थान में पानी सहेजना और सदुपयोग जीवनशैली का हिस्सा है जो अनुकरणीय है। •

जल संरक्षण की परंपरागत सौंदर्यपूर्ण शिल्प संस्थाएं

राजस्थान की बावड़ियां

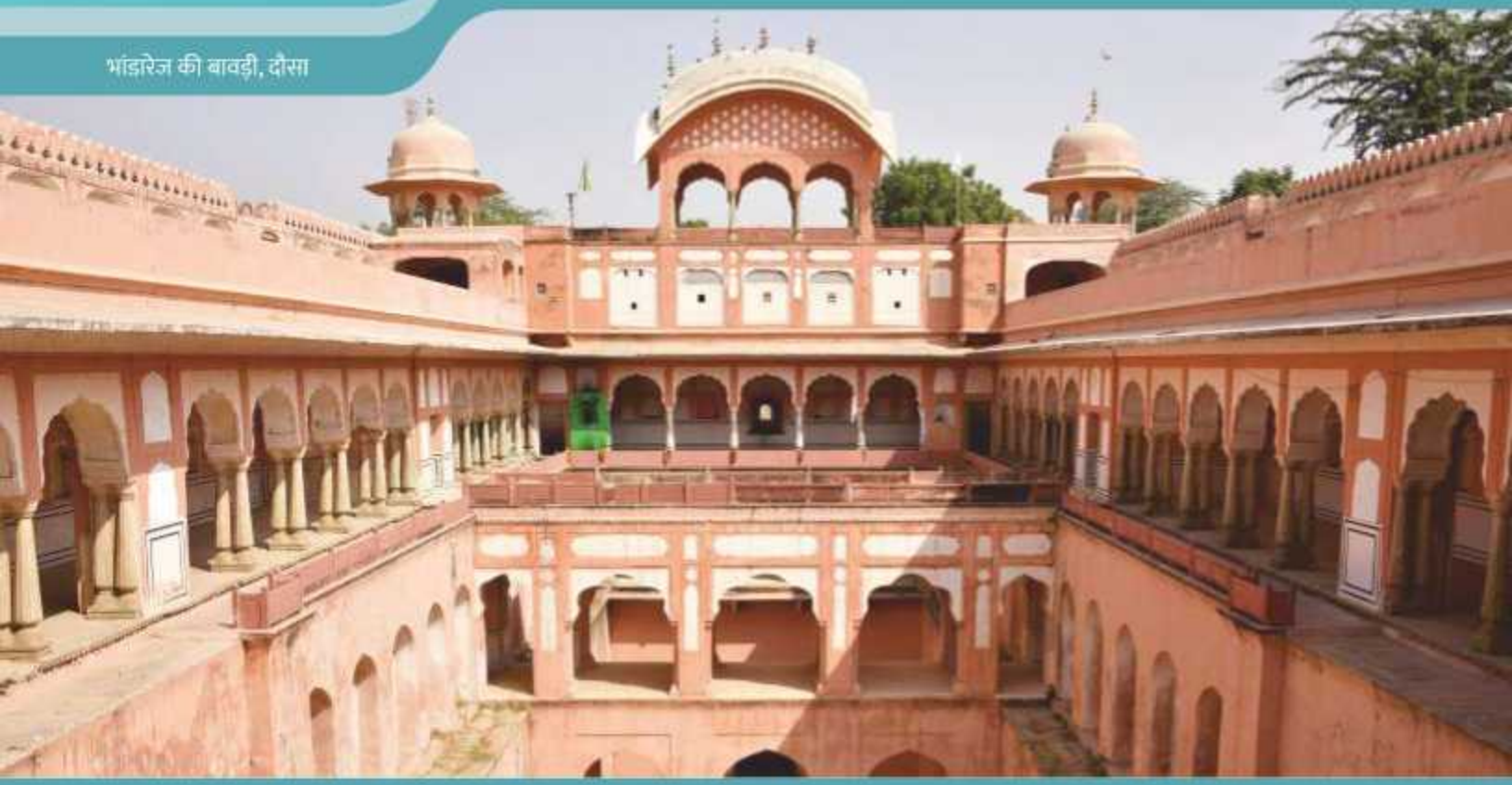

भांडारेज की बावड़ी, दौसा

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

जल के प्राचीन और मध्ययुगीन प्रबंधन को तत्कालीन शासन द्वारा व्यवस्थित व वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैधानिक नियमों के द्वारा विनियमित किया जाता था, जिसका सविस्तार वर्णन अथर्ववेद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में किया गया है। पौराणिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों में वापी, कूप और तड़ाग (बावड़ी, कुओं और तालाब) के विभिन्न प्रकारों, उनके निर्माण तथा रख-रखाव के तरीकों के साथ ही इनके निर्माण एवं नवीनीकरण के कारण व्यक्ति को प्राप्त होने वाले यश एवं पुण्यों का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में बावड़ी को वापिका, वापी, कर्कंधु, शकंधु आदि नामों से पुकारा जाता था।

राजस्थान भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक रहा है जहां पश्चिमी रेगिस्तान में अत्यंत कम वर्षा होती है। इसी कारण एक आम राजस्थानी के दैनिक जीवन में पानी वह बिंदु है, जिसके इर्द-गिर्द उसका जीवन घूमता है। पानी की इसी कमी के कारण राजस्थानियों ने सदैव ही उसके संरक्षण एवं भंडारण के लिए वैज्ञानिक नवाचार व प्रयोग किए हैं। राजस्थान के सभी समुदायों में बावड़ी बनवाने का कार्य हमेशा ही केंद्रीय स्थान पर रहा है। दूसरी ओर, राजस्थान में निजी तौर पर बनाई जाने वाली बावड़ियां सामुदायिक उपयोग के लिए खुली थीं। सहयोग व भाईचारे की भावना प्राचीन और मध्यकालीन जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं, जलाशय तथा बावड़ियां खुदवाना एक परोपकारी गतिविधि थी। इसी कारण राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा भी प्राचीन है।

अधिकांश बावड़ियां मंदिरों, किलों या मठों के नजदीक बनाई जाती थीं।

मंदिरों, महलों, किलों, छतरियों के अलावा राजस्थान की बावड़ियां भी अपने विशिष्ट स्थापत्य शिल्प के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान की बावड़ियां विभिन्न प्रकार से अलंकृत व सज्जित की गई हैं तथा ये उस समय के लोगों की कला के प्रति परिष्कृत सुरुचि की प्रतीक हैं। ये बावड़ियां गहरी, चौकोर तथा कई मंजिला होती हैं। ये सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों पर स्नान के लिए भी प्रयोग में आती थीं। शिलालेख सिद्ध करते हैं कि राहगीरों, राज-परिवारों, धार्मिक स्थलों, श्मशान, यज्ञ और शिकार करने, दान करने, अकाल राहत कार्यों आदि प्रयोजन से सराय, विश्रामगृह, बावड़ी, कुंड, कुओं आदि का निर्माण करवाया जाता था।

राजस्थान में करीब तीन हजार से ज्यादा बावड़ियां और कुंड हैं। बावड़ियों के निर्माण की प्रकृति एवं डिजाइन उस जगह की प्राकृतिक स्थितियों, वर्षा की मात्रा, भूमिगत जल स्तर, मिट्टी के प्रकार, निर्माण करने वाले की आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करती थी। शुरुआती युग में ये साधारण संरचनाएं थीं, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया ये महीन कलात्मक उत्कीर्ण से युक्त मूर्तियों व कलाकृतियों की साज-सज्जा के साथ विकसित होकर मनभावन एवं कलात्मक होती गईं। इनका डिजाइन और संरचनात्मक अलंकरण उन क्षेत्रों की विशिष्ट शैली को दर्शाते हैं जिनमें इनका निर्माण हुआ है।

पश्चिम में बीकानेर से कच्छ के रण के तट तक के कुएं एवं बावड़ियां आकार में भिन्न होती हैं और घाटों से घिरी हुई हैं तथा पानी के लिए जलग्रहण क्षेत्र में नीचे की ओर जाती हुई हैं। अरावली के पहाड़ी पथ में बावड़ियां अत्यधिक कौशल युक्त कलात्मक वास्तुकला की अनुपम कृतियां हैं।

बूंदी, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा और जयपुर क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन कुंडों के आसपास कलात्मक सीढ़ियां और स्तंभ के मनोहारी अलंकरण अत्यंत आकर्षक हैं। यहां की बावड़ियों के डिजाइन लोगों द्वारा दिल खोलकर खर्च के साथ बनाये गए। जलस्रोतों में उत्कृष्ट नक्काशियों, मेहराब, बरामदों और प्रस्तर उत्कीर्णन करने का कार्य किया गया है।

राजस्थान में बावड़ी अथवा बाव का तात्पर्य एक विशेष प्रकार के जल स्थापत्य से हैं जिसमें एक गहरा कुआं अथवा एक बड़ा कुंड होता है। इसमें पानी की सतह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, जिसे सीढ़ीयों वाला कुआं (stepwell) भी कहते हैं। इन पर अलंकृत द्वार, सुंदर तोरण तथा देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। देश में बावड़ियों का प्रचलन राजस्थान में तथा गुजरात में सबसे अधिक है। तालाब का ही सुव्यवस्थित और सुसज्जित रूप कुंड या बावड़ी होता है।

बावड़ियां के विभिन्न प्रकार

प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी के संस्कृत रूप वापी के उल्लेख प्रथम शताब्दी में मिलते हैं। राजस्थान की प्रारंभिक बावड़ियों में अमलेश्वर की बावड़ी शुंगकालीन बावड़ी है। बावड़ियां आस्था का प्रतीक होती थीं। राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी निर्माण राव जोधा ने करवाया था। भोज द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ 'अपराजितपृच्छा' में बावड़ियों के चार प्रकार बताए गए हैं :

1. **नंदा :** इसमें एक या दो द्वार तथा तीन कूट होते हैं।
2. **भद्रा :** दो दीवारों एवं षट कूट वाली सुंदर बावड़ी।

बूंदी की बावड़ी

3. **जया :** इस प्रकार की दुर्लभ बावड़ी जया में तीन द्वार व नौ कूट होते थे।
4. **सर्वतोमुख :** इसमें चार द्वार तथा बारह सुंदर कोट होते थे।

बावड़ियों के निर्माण में बंजारों का सर्वाधिक योगदान रहा है। कालिदास के मेघदूत में यक्ष द्वारा अपने घर के भीतर बावड़ी का वर्णन किया है। इसी प्रकार सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हनुमान ने ऐसी बावड़ी देखी जिनमें पीले रंग के कमल खिले हुए थे। आभानेरी (बांदीकुई, दौसा) की चांद बावड़ी, ओसियां (जोधपुर) की बावड़ी तथा भीनमाल (जालोर) की बावड़ी में भीतरी आवास आज भी देखा जा सकता है। छोटी काशी बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां हैं, इसलिए बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है

चांद बावड़ी, आभानेरी

बांदीकुई के समीप आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक है। यह भारत की प्राचीनतम बावड़ियों में से है जो अब भी सजीव हैं। भारत की इस सर्वाधिक गहरी बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा या चंद्रा ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में करवाया था। चांद बावड़ी सभी बावड़ियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है।

चांद बावड़ी के अंदर बनी आकर्षक सीढ़ियां कलात्मक और पुरातत्व कला का शानदार उदाहरण हैं। 13 मंजिल की इस बावड़ी के अंदर 3,500 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। यहां एक बहुत छोटा सा कमरा भी है जिसे "अंधेरी उजाला" के नाम से जाना जाता है। बावड़ी की सबसे नीचे की दो ताखों में गणेश एवं महिषासुरमर्दिनी की भव्य प्रतिमाएं हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।

चौकोर आकार में बनी यह बावड़ी हर ओर से 35 मीटर लंबी है। चार कोनों में से तीन कोनों में सीढ़ियां हैं, जो गहराई तक पहुंचती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु रुखी-सूखी है और उस समय यहां पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी एक साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इस बावड़ी के नीचे एक लंबी सुरंग है जो भांडारेज स्थित बड़ी बावड़ी से होती हुई आलूदा गांव के कुंड कुबाणा तक जाती है।

रानी जी की बावड़ी बूंदी

बूंदी में तकरीबन 71 छोटी-बड़ी बावड़ियां हैं। बूंदी की सुंदरतम 'रानी जी की बावड़ी' की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है। इसमें लगे सर्पाकार तोरणों की कलात्मक पच्चीकारी अत्यंत आकर्षक है। बावड़ी की दीवारों में विष्णु के अवतार मत्स्य, कच्छप वराह नृसिंह, वामन, इंद्र, सूर्य, शिव, पार्वती और गजलक्ष्मी आदि देवी-देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। इस कलात्मक बावड़ी में प्रवेश के लिए तीन दरवाजे हैं। बावड़ी की गहराई लगभग 46 मीटर है। इस अनुपम बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी राजमाता नाथावती ने 1699 ई. में अपने पुत्र बुध सिंह के शासनकाल में करवाया था। रानी जी की बावड़ी के अंदर जाने के लिए सौ से अधिक सीढ़ियां बनी हैं। इसकी स्थापत्य कला बहुत ही दर्शनीय व आकर्षक है। यह मुगल एवं राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह कलात्मक बावड़ी उत्तर मध्य युग की अनुपम देन है। इस बावड़ी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इमारत का दर्जा प्रदान किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया है एवं इसके पास में एक उद्यान भी विकसित किया है। इसके अलावा बूंदी में स्थित चंपा बाग की बावड़ी गर्मी में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गुलाब बावड़ी कुंडली आकार की है और दिन के तीसरे पहर में अपने आप ही पानी से भर जाती है।

बूंदी की प्रमुख बावड़ियां

- साबू नाथ की बावड़ी
- दमरा व्यास बावड़ी
- धाबाई जी बावड़ी नानकपुरिया
- मनोहर डाकरा बावड़ी
- मोचियों की बावड़ी
- दीवान की बावड़ी
- माता की बावड़ी
- भावलदी बावड़ी
- नाथ की बावड़ी
- माननासी बावड़ी
- मेघनाथ की बावड़ी
- नाहर घुस की बावड़ी
- गुलाब बावडी
- पठान की बावड़ी
- सांमरिया की बावड़ी
- बालचंद पाड़ा की बावड़ी
- अनारकली की बावड़ी
- श्याम बावड़ी
- चेन राय करीला की बावड़ी
- भिस्तियों की बावड़ी-एल (L) बावड़ी

नीमराणा की बावड़ी

इसका निर्माण राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में नीमराना, अलवर में करवाया था। यह नौ मंजिला है। इसकी लंबाई 250 फीट व चौड़ाई 80 फीट है। इसमें समय पर एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता था। मध्यकालीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना यह है कि इस नौ मंजिला बावड़ी के निचले भाग में तापमान 19 डिग्री कम हो जाता है।

पन्ना मीना की बावड़ी, आमेर

17वीं सदी की अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक ओर जयगढ़, आमेर दुर्ग व दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। यह अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। चांद बावड़ी तथा हाड़ी रानी की बावड़ी के समान इसमें भी तीन तरफ सीढ़ियां है। इसके चारों किनारों पर छोटी-छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं।

हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडारायसिंह

बेजोड़ स्थापत्य कला के इस नमूने का निर्माण बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी ने लगभग 16वीं शताब्दी में करवाया था जिनका विवाह सोलंकी शासक से हुआ था। इसके एक ओर बने अनूठे विश्राम कक्ष अपने आकार ऊंचाई व ठंडक के कारण जाने जाते हैं।

हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडारायसिंह

रंगमहल की बावड़ी, सूरतगढ़

रंगमहल (सूरतगढ़) किसी समय यौधेय गणराज्य की राजधानी था। पहले सिकंदर के आक्रमण और, उसके बाद हूणों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो गया। उत्खनन में यहां से एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 2 फीट लंबी तथा 2 फीट चौड़ी ईंटें लगी हैं। यह बावड़ी इस बात का प्रतीक है कि शकों के भारत आगमन के बाद भी रंगमहल सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक अपने साथ भारत लाए थे।

भीकाजी की बावड़ी, अजमेर

अजमेर से 18 किमी पूर्वोत्तर दिशा में अजमेर जयपुर रोड पर स्थित यह बावड़ी भीकाजी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। इसमें संगमरमर पर हिजरी 1024 (1615 ई.) का फारसी लेख उत्कीर्ण है। अभिलेख फलक पर उकडू बैठा हुआ हाथी, अंकुश एवं त्रिशूल बना है। पुरातात्विक महत्व की इस बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं।

भांडारेज की बावड़ी

भांडारेज दौसा में स्थित एक बावड़ी है, जो राजस्थान की प्राचीन शिल्पकला का सुंदर उदाहरण है। यह एक तीन मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। भांडारेज की बावड़ी को "बड़ी बावड़ी" भी कहते हैं। इस बावड़ी में पानी की सतह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों के ऊपर बरामदे तथा पीछे की ऊपरी मंजिल पर अंधेरी उजाली है जहां पहुंचने पर दर्शक को अद्भुत रोमांच की अनुभूति होती है। यह बावड़ी अपनी कलात्मक छतरियों, मेहराबों और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।

बाटाडू की कुआं बावड़ी

बाड़मेर जिले की बायतु पंचायत समिति के ग्राम बाटाडू में आधुनिक संगमरमर से निर्मित कुएं पर की गई शिल्पकला दर्शनीय है।

ओसियां बावड़ी, जोधपुर

ओसियां बावड़ी जोधपुर से 65 किमी की दूरी पर स्थित है, जिसमें एक तरफ मंदिरों का समूह तथा दूसरी तरफ रेगिस्तान है। ओसियां में मां सच्चियाय का भव्य मंदिर बना हुआ है तथा यहां पूर्व में 108 मंदिर थे। ओसियां बावड़ी देसी-विदेशी पर्यटकों को मंदिर एवं स्मारकों की स्थापत्य कला के कारण आकर्षित करती है। वर्तमान में ओसियां में 18 स्मारक एवं दो बावड़ी स्थित हैं। मंदिरों में एक महावीर स्वामी का जैन व हिंदू मंदिर है। इनमें सूर्य मंदिर, हरिहर के 3 मंदिर, विष्णु जी के मंदिर, शीतला माता का मंदिर, शिव मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर और सबसे विशाल सच्चियाय माता का मंदिर है।

जोधपुर की प्रमुख बावड़ियां

- नई सड़क बावड़ी
- नापर जी की बावड़ी
- व्यास बावड़ी
- सुमन वोहरा की बावड़ी
- अनारा बावड़ी
- धाय बावड़ी
- हाथी बावड़ी
- राजाराम की बावड़ी
- शिव बावड़ी
- राम बावड़ी
- एक चट्टान बावड़ी
- मंडोर बावड़ी
- गोररूंधा बावड़ी
- चतानियां की बावड़ी
- जालाप बावड़ी
- नैनसी बावड़ी
- ईदगाह बावड़ी
- खरबूजा बावड़ी
- व्यास जी की बावड़ी
- पांचवा मंजीषा बावड़ी
- रघुनाथ बावड़ी
- तापी बावड़ी

दूध बावड़ी, माउंट आबू

दूध बावड़ी अथर देवी मंदिर की तलहटी में स्थित है जो एक पवित्र कुआं है और माउंट आबू के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका नाम दूध बावड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि इस कुएं में जो पानी है उसका रंग दूध की तरह है। इस कुएं के पानी के रंग के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी ही किंवदंती के अनुसार यह कुआं देवी-देवताओं के लिए दूध का स्रोत है। स्थानीय निवासियों द्वारा इस पानी को पवित्र माना जाता है। अनेक लोग इस कुएं को गायों की देवी कामधेनु का प्रतीक भी मानते हैं।

हाड़ी रानी की बावड़ी

टोडारायसिंह (टोंक) में विशालपुर में हाड़ी रानी की विशाल बावड़ी स्थित है।

गड़सीसर सरोवर की बावड़ी

जैसलमेर में इस सरोवर का निर्माण रावल गड़सी के शासनकाल में सन् 1340 में करवाया गया। इस कृत्रिम सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार 'टीलों की पिरोल' के रूप में विख्यात है।

मेड़तनी की बावड़ी, झुंझुनूं

मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनूं में स्थित है। इसका निर्माण शार्दूल सिंह झुंझुनूं के मरणोपरांत उनकी पत्नी बख्त कंवर ने अपने पति की याद कायम रखने के लिए पीपल चौक तथा मनसा देवी मंदिर के बीच करवाया था। खेतानों की बावड़ी, जीतमल का जोहड़ा, तुलस्यानों की बावड़ी, लोहार्गल तीर्थस्थल पर बनी चेतनदास की बावड़ी तथा नवलगढ़ कस्बे की बावड़ी झुंझुनूं जिले की अन्य प्रमुख बावड़ियां हैं। •

मरुस्थल में जल संग्रहण की अनूठी तकनीक खड़ीन

राजस्थान के सुदूर पश्चिमी इलाके जैसलमेर में सदियों से जल संग्रहण के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसे खड़ीन कहते हैं। यह तकनीक जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में यहां के निवासियों के लिए खेती करने हेतु बहुत ही कारगर साबित हुई है।

दुनिया के अलग-अलग इलाकों में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए खेती करने और जल संग्रहण करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए अलग-अलग तरह की तकनीक अपनाई जाती हैं। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी इलाके जैसलमेर में सदियों से जल संग्रहण के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसे खड़ीन कहते हैं। यह तकनीक जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में यहां के निवासियों के लिए खेती करने हेतु बहुत ही कारगर साबित हुई है।

धीरज कुमार दवे
जनसम्पर्क अधिकारी

ऐसे तैयार होते हैं खड़ीन

खड़ीन के पहाड़ी ढलान पर कुछ फीट ऊंचे बांध बनाकर पानी को रोका जाता है जिसमें एक सिरे पर पत्थर से एक मजबूत दीवार बनाई जाती है जिसे पंखा कहते हैं और इस पंखे से कुछ दूर तक पत्थर की खड़ीन बनाई जाती है। ढलान से एक खड़ीन का पानी भरने पर पानी उसी खड़ीन से जुड़े हुए दूसरे खड़ीन में चरणबद्ध रूप से भरता जाता है। इस तकनीक में जल संग्रहण से जमीन की नमी बरकरार रखी जाती है। यहां की मिट्टी का गुण भी ऐसा है कि अगर ऊपरी धरातल पर पानी सूख भी जाए तो गहराई में नमी बरकरार रहती है। जैसलमेर में सर्दी भी खूब पड़ती है तो कई बार मावठ की वजह से भी पैदावार बढ़ती है।

माना जाता है कि इस तकनीक की शुरुआत यहां के पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। उस वक्त इस क्षेत्र से गुजरने वाली एक नहर के किनारे पालीवाल ब्राह्मण आकर बसे और उन्होंने खड़ीन बनाए। जब-जब इस क्षेत्र में बाढ़ आती, तब पानी इन

खड़ीन में भर जाता जिससे अच्छी पैदावार होती।

स्थानीय जल संग्रहण पद्धतियों के जानकार डॉ. दीपक चतुर्वेदी बताते हैं कि जैसलमेर जिले में कम और अनियमित वर्षा, रेत के टीलों के साथ शुष्क रेतीली मिट्टी के इलाके, बहुत अधिक वाष्पीकरणीय स्थितियों के कारण फसल की उपज कम होती है। बरसात का मौसम जून से सितंबर तक की अवधि तक ही सीमित होता है, जब कुल वार्षिक वर्षा का 90-95 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन स्थितियों में फसल की खड़ीन प्रणाली सबसे अधिक प्रासंगिक है।

जैसलमेर क्षेत्र मे वर्षा का पानी घेर कर बांधों मे लाया जाता है। घिरे हुए बांधों को यहां की भाषा मे खड़ीन कहते हैं। खड़ीन एक अपवाह प्रणाली है जो जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा जल संचयन, खरीफ मौसम के दौरान खेत की भूमि पर पानी को मोड़ने व एकत्र करने और रबी के दौरान इस भूमि पर फसल पैदा करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषता एक बहुत लंबा (100-300 मीटर) मिट्टी का तटबंध है जो निचली पहाड़ी ढलानों पर बनी हुई है और बजरीदार ऊपरी भूमि के नीचे स्थित है। स्लुइस व स्पिलवे अतिरिक्त पानी को निकालने में सहायक होती हैं।

खड़ीन के अधिकतम उपयोग के मौजूदा प्रयास

इन खड़ीनों में गेहूं एवं चना पैदा किया जाता है। जैसलमेर जिले में निर्मित 19 खड़ीन हैं। यह विधि वर्ष में कम से कम एक फसल सुनिश्चित करती है। जैसलमेर जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खड़ीन क्षेत्रों में प्रलेखन एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत "खड़ीन क्षेत्रों में खेती प्रणाली के प्रलेखन, चना एवं गेहूं की फसलों में किस्मों एवं पोषक तत्व प्रबंधन का मूल्यांकन" विषय पर एक योजना चलाई गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सामाजिक व आर्थिक रूपरेखा और कृषि क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता, वनस्पतियों के प्रलेखन का विश्लेषण, जैसलमेर क्षेत्र के खड़ीन क्षेत्रों के कृषि प्रणालियों के मॉडल का प्रलेखन, खड़ीन क्षेत्रों के लिए गेहूं और चने की उच्च उपज वाली किस्मों का मूल्यांकन, खड़ीन क्षेत्रों की मिट्टी की उर्वकरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों की आधारित मात्रा का अनुकूलन तथा प्रदर्शनों से बाहर रहने वाले किसानों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है।

इस योजना से खड़ीन क्षेत्रों के किसानों में उन्नत किस्म के बीजों के प्रति जागरूकता आई एवं इस योजना के अंतर्गत वितरित किए गए चने एवं गेहूं की किस्मों से उन्हें उनकी पारंपरिक किस्मों से अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता की फसल का उत्पादन हुआ जिससे उन्हें हर वर्ष खड़ीन से प्राप्त होने वाली उपज से ज्यादा उपज प्राप्त हुई एवं उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ। ये खड़ीन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर सामूहिक संपत्ति होते हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि इस तकनीक से कृषि क्षेत्र में उत्पादन के साथ-साथ सामूहिक मेलजोल, प्रेम और संगठन में काम करने की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। •

महंगाई राहत कैंप में मिली राहत

छाया : सुजस

सूर्यनगरी में जल स्थापत्य की अनुपम मिसाल

झालरा

पग पूंगल धड़ कोटड़े, उदरज बीकानेर।
भूलो चूको जोधपुर, ठावो जैसलमेर।।

अभय सिंह
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान में अकाल के बारे में प्रचलित इस कहावत के मुताबिक अकाल कहता है कि उसके पैर पूगल (बीकानेर) में, धड़ कोटड़ा (मारवाड़) में और पेट बीकानेर में है। कभी-कभी वह जोधपुर में रहता है, लेकिन उसका स्थाई निवास जैसलमेर में है।

इस कहावत से परिलक्षित होता हैं कि अकाल मारवाड़ अंचल में भयावह स्वरूप में सदियों से विद्यमान रहा है। पश्चिमी थार मरुस्थल में जल की महत्ता स्वयंसिद्ध है। एक ओर अरावली पर्वतमाला मानसूनी वर्षा को मारवाड़ तक पहुंचने नहीं देती, वहीं अत्यधिक गर्मी जल स्रोतों को सुखा देती है। इन विकट परिस्थितियों में मारवाड़ में जल संग्रहण और संरक्षण के लिए कई भगीरथी प्रयास किए गए, जिनके परिणामस्वरूप मारवाड़ में जल संरचनाओं के साथ स्थापत्य के अनुपम उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। जल संकट और अकाल का सामना करते हुए यहां के शासकों और आमजन ने कुशल जल प्रबंधन की व्यवस्था की और उसके उचित ढंग से उपयोग को सुनिश्चित किया। इनकी बदौलत मारवाड़ के लोगों को यह जीवन अमृत सर्वसुलभ हो पाया।

इसी दिशा में संपूर्ण मारवाड़ में कुओं, तालाबों, बावड़ियों और झीलों का निर्माण किया गया। इसी तरह जोधपुर शहर में जल संरक्षण और शिल्प सौष्ठव के सहगामी के रूप में झालरे निर्मित हुए। झालरा एक बावड़ी का ही भव्य रूप है। इसकी खुदाई तीनों या चारों ओर से ढलान में की जाती थी और भू-जल का स्रोत आने तक गहरी सीधी खुदाई भी होती रहती थी। फिर तीन ओर ढलानों में कलात्मक सीढ़ियों का निर्माण होता था। झालरों की दीवारों पर मूर्तियां, झरोखे, आले, मेहराब, छतरी, महल आदि बनाकर उन्हें भव्य और कलात्मक बनाया जाता था। इस प्रकार झालरा बावड़ी की अपेक्षा विस्तृत होता है। अमूमन तीन ओर सीढ़ियां और एक तरफ ऊंचा मेहराबयुक्त दो-तीन मंजिला महलनुमा भवन बनाया जाता था, जो सांस्कृतिक आयोजन, त्योहार, भोज और मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता था। इस ऊंचे भवन का उपयोग अधिक मात्रा में पानी निकालने हेतु रहट लगाने में भी होता था। ग्रीष्मकाल में जब इनमें ऋतु रहट चलते थे, तो रहट से गिरने वाला जल वातानुकूलन का कार्य भी करता था क्योंकि रहट से नीचे गिरने वाला जल वहां आने वाली गर्म हवाओं को ठंडा कर देता था। झालरों में ऊंचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त होता है। झालरों का जल धार्मिक रीति-रिवाजों को पूर्ण करने, सामूहिक स्नान एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। झालरों का आकार आयताकार एवं वर्गाकार होता है, जिनके तीन ओर

सीढ़ियां बनी होती हैं।

झालरा शब्द का उपयोग जोधपुर के अलावा अन्यत्र नहीं मिलता है। साहित्यिक दृष्टि से इस शब्द का उपयोग "शिवकरण पंचोली की बही" में सर्वप्रथम हुआ है, जिसमें विक्रम संवत 1730 में बने पंचोली केसरीसिंह के झालरे का उल्लेख है।

झालरा शब्द संस्कृत के 'झल्लरी' से बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के किनारे पर शोभा के लिए बनाया हुआ लटकने वाला किनारा। संस्कृत ग्रंथ 'भीमप्रबंध महाकाव्यम' में बावड़ी के लिए 'झल्लरिका' शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह मारवाड़ी भाषा में झालरा शब्द स्त्री के गले के अलंकृत हार के लिए भी प्रयुक्त होता है। जब हम बावड़ी को तीन ओर से कलात्मक सीढ़ियों द्वारा घेर लेते हैं तो वह भी हार की तरह प्रतीत होती है।

जोधपुर के प्रमुख झालरे इस प्रकार हैं :

पंचोली केसरीसिंह का झालरा

यह पहला निर्मित झालरा माना जाता है। इसका निर्माण महाराजा जसवंतसिंह प्रथम के दीवान पंचोली केसरीसिंह रामचंदोत ने करवाया था। यह राईकाबाग महल के पूर्व दिशा के दरवाजे के पास स्थित है।

तूरजी का झालरा

यह जोधपुर में कला और सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट झालरा है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी जैकंवर तुंवरजी द्वारा करवाया गया। यह पुराने शहर में मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। झालरे की दीवारों पर नृत्यमुद्रा में हाथियों की नक्काशी की गई है। पश्चिमी दिशा में गौमुख और सिंहमुख बने हुए हैं। मेहराबयुक्त ऊंचा उठा बरामदा, मेहराब के दोनों ओर झरोखे, मेहराबदार संरचना के ऊपर हवादार बरामदा, तीनों ओर सीढियां, सीढ़ियों की दीवारों पर मूर्तियां रखने के लिए आलों का निर्माण इसकी विशेषता है। झालरे की गहराई लगभग 200 फीट है। इसमें भूजल के साथ पंचेटिया पहाड़ी से वर्षा जल संग्रहित होता है।

मायलाबाग का (महिला बाग) झालरा

इसका निर्माण गुलाबसागर झील के पास महाराजा विजयसिंह की पासवान गुलाबराय ने करवाया था। यह झालरा बाग के भीतर था। स्थानीय भाषा में 'मायला' का अर्थ अंदर या भीतर होता है, इसलिए मायलाबाग झालरा कहा गया। यह बोल-चाल में महिलाबाग झालरा के नाम से संबोधित किया गया। तीन मंजिला मुख्य भवन, सबसे नीचे मेहराबदार द्वार, कलात्मक शीर्ष वाले स्तंभ, छत पर जालीदार पत्थर की रेलिंग और चारों दिशाओं में गोलगुंबद वाली चार छतरियां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।

सुखदेव तिवारी का झालरा

यह झालरा मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। झालरे के पास कीर्तिस्तंभ के अनुसार अश्व चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता त्रिवाड़ी सुखदेव चतुर्भुजोत के पुत्र उदयराम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। झालरा लगभग 50 फीट गहरा है। चारों दिशाओं में देवी-देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं।

जाड़ेची जी का झालरा

चांदपोल के बाहर स्थित इस झालरे का निर्माण महाराजा अजीतसिंह की रानी बदनकंवर जाड़ेची द्वारा करवाया गया था। अन्य झालरों के मुकाबले यह झालरा आकार में छोटा है। •

भू-जल बचाने के समेकित प्रयास

बूंद-बूंद बचत को बनाना होगा आदत

भारजा नाड़ी,

दिनेश कुमार शर्मा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

पानी की एक-एक बूंद कितनी कीमती है, यह राजस्थान के लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। अपनी भौगोलिक संरचना और परिस्थितिजन्य विषमताओं के चलते नीर के लिए मरुभूमि हमेशा प्यासी ही रही है। देश के सतही जल का महज 1.16 प्रतिशत और भूमिगत जल का महज 1.72 प्रतिशत राज्य के हिस्से में आता है। जबकि देश की 5.67 प्रतिशत आबादी यहां निवास करती है और राज्य में देश का 10.41 प्रतिशत भू-भाग है। सतही जल स्रोतों की कमी के कारण राज्य में भू-जल पर निर्भरता अधिक है।

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट का आकलन

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष जारी की गई नवीनतम सालाना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वार्षिक भू-जल रिचार्ज 12.13 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) और दोहन योग्य भू-जल संसाधन 10.96 बीसीएम आंका गया। इसकी तुलना में भू-जल निकासी 16.56 बीसीएम रही। अर्थात राज्य में 151.07 प्रतिशतकी दर से भू-जल दोहन हुआ।

जनसंख्या में तीव्र रूप से हो रही वृद्धि, कृषि विकास, बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि वे कारक हैं जिनके चलते भू-जल दोहन में वृद्धि हो रही है। अधिक दोहन से जलभृत सूखते जा रहे हैं। साल 1984 में भू-जल दोहन की जो दर मात्र 35 फीसदी थी। वह नई सदी के आगमन के साथ ही वर्ष 2001 में 100 फीसदी को पार कर 104.26 फीसदी पर पहुंच गई, और आज 151.07 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर है।

रिपोर्ट में 7 नई शहरी यूनिट्स को शामिल कर कुल 302 यूनिट्स (ब्लॉक्स) का आकलन किया गया। इनमें से 219 ब्लॉक्स (72.51 प्रतिशत) अतिदोहित श्रेणी यानी डार्क जोन में हैं। इसी प्रकार 22 ब्लॉक्स (7.3 प्रतिशत) क्रिटिकल और 20 ब्लॉक्स (6.6 प्रतिशत) सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। केवल 38 ब्लॉक्स (12.58 प्रतिशत) सुरक्षित श्रेणी में हैं। जबकि 3 ब्लॉक्स (0.99 प्रतिशत) लवणीय होने के कारण इनका रिपोर्ट में आकलन नहीं किया गया। वर्ष 1984 में जब पहली बार 236 ब्लॉक्स का असेसमेंट किया गया था, तब 203 ब्लॉक्स सुरक्षित श्रेणी में और केवल 12 ब्लॉक्स अतिदोहित श्रेणी में थे।

भू-जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार के प्रयास

भू-जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रयास वृहद् पैमाने पर किए जा रहे हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना भू-जल स्तर बढ़ाने की दिशा में कारगर प्रयास और प्रभावी पहल है। 22 मार्च, 2023 से शुरू हुए योजना के द्वितीय चरण में 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों के 4,600 गांवों में 2,600 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण कार्य कराए जाएंगे। ये कार्य वर्षा जल संचय, वर्षा जल संग्रहण, एनिकट चेक डैम, चारागाह विकास कार्य, कृषि भूमि में फार्म पॉण्ड, टांके आदि से संबंधित हैं। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत किए गए वर्षा जल संग्रहण कार्यों से भू-जल तालिका में बढ़ोतरी हुई और किसानों को कृषि कार्य हेतु पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। योजना के प्रथम चरण में अगस्त, 2019 से जून, 2022 तक 3,931 गांवों में 1,557 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 1 लाख 31 हजार जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका था।

इसके अलावा अटल भू-जल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना आदि के प्रभावी क्रियान्वयन से भी भूमिगत जल सहेजने में मदद मिल रही है। प्रदेश में भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया चल रही है। सतही जल का कुशल प्रबंधन भी भू-जल पर निर्भरता कम कर रहा है। वहीं, इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है।

प्रदेशवासियों को बनना होगा भागीदार

राज्य सरकार भू-जल के संरक्षण, प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों को भी इन भगीरथी प्रयासों में भागीदार बनने की आवश्यकता है। राजस्थान में वर्षा जल संचयन की पुरानी परंपरा रही है, हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। बहुमंजिला एवं बड़े भवनों के साथ ही कम आकार के भवनों मे भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए। किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाई जाएं, जिनमें पानी का कम

माही बांध

से कम उपयोग हो। फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया जाए। इससे पानी भी कम खर्च होता है और फसल उत्पादन भी बढ़ता है। समय रहते नदियों व तालाबों की सफाई भी कराई जानी चाहिए। परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग सहित जल संरक्षण के लिए सामुदायिक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। परिस्थितियों को देखते हुए अधिक पानी के उपयोग पर आधारित जीवन शैली में बदलाव की भी आवश्यकता है। वहीं, अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण दूरगामी और सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।

बारिश का पानी संग्रहित करने के उपाय

वर्षा जल सहेजकर हम भू-जल स्तर बढ़ा सकते हैं। बारिश का पानी संगृहीत करने के विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- **सीधे जमीन के अंदर :** इसमें बारिश के पानी को एक गड्ढे के माध्यम से सीधे जमीन में उतार दिया जाता है।
- **खाई बनाकर रिचार्जिंग :** इसमें बड़े संस्थान के परिसरों में बाउंड्री वॉल के साथ-साथ रिचार्ज ट्रेंच बनाकर पानी को जमीन में उतारा जाता है।
- **कुओं या ट्यूबवेल में पानी उतारना :** इसमें छतों से पाइप के द्वारा वर्षा जल को घर या पास के किसी कुएं अथवा ट्यूबवेल में उतारा जाता है।
- **टैंक में जमा करना :** बारिश के पानी को टैंक में जमा कर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस विधि से बरसाती पानी का लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है।

खुद बनवा सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम

थोड़ी-सी जानकारी लेकर आप खुद भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवा सकते हैं। इसमें घर में एक कच्चा टैंक बनाया जाएगा। उसे छत की पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। जो भी बारिश का पानी होगा वह उस गड्ढे में जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो व्यक्ति इस बारिश के पानी का उपयोग कर पाएगा और दूसरा भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। गड्ढे के आकार का भी एक सामान्य फॉर्मूला (छत का एरिया X 0.8 X 0.025) निर्धारित है। मान लें कि छत का एरिया 100 मीटर है तो 100 X 0.8 X 0.025 = 2 क्यूबिक मीटर आयतन वाला गड्ढा बनेगा। इस पिट की गहराई 2 मीटर होगी। लंबाई और चौड़ाई 1-1 मीटर होगी।

जल संचय की तकनीकों को अपनाने के साथ ही हमें पानी की एक-एक बूंद सहेजने की आदत डालनी होगी। भले ही धरती पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो लेकिन उपयोग के लिए यह संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में है। •

पाणी ढूळै म्हारो जी बळै

राजस्थान के जनजीवन और लोक व्यवहार में गुंथी जल प्रबंधन की रीतियां

चंद्रशेखर पारीक
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

जल प्रकृति की ऐसी अनुपम संपदा है, जिसके हर अंश में प्राणदायिनी शक्ति है। जहां जल है, वहां जीवन है। प्राण और स्पंदन है, गति है, सृष्टि है, संक्षेप में जल जीवन का मूलाधार है। जहां जल नहीं, वहां सबकुछ निष्प्राण और निश्चेष्ट है। किसी राष्ट्र या राज्य में जल के बिना विकास की कल्पना असंभव है। इसलिए जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों में भी जल प्रबंधन का पता चलता है। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भी जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों में तथा जैन बौद्ध साहित्य में नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं और झीलों का विवरण मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ अभिलेख, सभी में जलाशय निर्माण का विवरण मिलता है।

हमारे साहित्य में भी कहा गया है...

> रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
> पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।।

विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, उनकी प्रकृति एक-सी है, पानी कम और गर्मी अधिक। इसी के चलते बसावट कम और जीवन बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन राजस्थान के जिंदादिल और जीवटता वाले लोगों ने प्रकृति के इस नियम का अपवाद तैयार कर लिया। इसके फलस्वरूप यहां शून्यता नहीं, सरसता मिलती है। दूभर परिस्थितियों के बीच भी यहां जनमानस अपेक्षाकृत अधिक सजीला और रंगीला है। राजस्थान के रंगीले और जीवंत होने का रहस्य यहां के जनजीवन और लोक व्यवहार में गुंथी जल प्रबंधन की रीतियों में छुपा है।

राजस्थान के कर्मठ लोगों ने कभी प्रकृति की इस कृपणता का रोना नहीं रोया, भाग्य को नहीं कोसा बल्कि इस मुश्किल को भी वरदान मानकर योद्धा की तरह प्रकृति प्रदत्त उस चुनौती का सामना किया। एक मान्यता के अनुसार बहता हुआ जल निर्मल माना जाता है किंतु राजस्थान में बहते जल के स्रोत बहुत कम हैं। इस वजह से यहां के लोगों ने संगठित होकर वर्षा की एक-एक बूंद का संग्रह करने के लिए गांव-घरों में कुंडी, कुंड, टांका और बावड़ी आदि बनाकर उसे बड़े जतन के साथ वर्षभर और उससे भी अधिक समय के लिए उपयोग करने की ऐसी भव्य परंपरा विकसित की, जिसकी मिसाल कहीं-कहीं मिलती है।

लोक व्यवहार में जल की बचत

आधुनिक समय में पानी बचाने के तकनीकी समाधान जैसे एफिशिएंट वॉश बेसिन टैप, टॉयलेट फ्लश टैंक, लो-फ्लो शावर और स्मार्ट मीटर उपयोगी तो हैं, पर सहज सुलभ नहीं हैं और इनके लाभों पर भी हमारा व्यवहार भारी पड़ता है। इसके उलट सैकड़ों वर्षों से हमारे ग्रामीण जीवन में लोक व्यवहार, रीति-रिवाज और परंपराएं जल संरक्षण का मजबूत आधार रही हैं। राजस्थान में कहावत मशहूर है कि

> घी ढूळै, म्हारे कांई नी बळै ।
> पाणी ढूळै, म्हारो जी बळ ॥

यहां पानी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि जैसलमेर जैसे अल्प वर्षा वाले जिलों में खाट पर बैठकर नहाने का चलन रहा, जिससे पानी को नीचे बड़े बरतन में सहेज कर अन्य किसी कार्य में उपयोग लिया जा सके। इसी प्रकार राजस्थान के खानपान में घी का बहुतायत में प्रयोग भी कहीं न कहीं पानी की कमी से जुड़ा है। यहां के व्यंजनों में अधिकांश कम से कम पानी या छाछ-दही-घी इत्यादि से तैयार होने वाले ही मिलेंगे। बर्तनों की सफाई राख से करना, खेत में मतीरों की बेल आवश्यक रूप से लगाना आदि पानी के किफायती इस्तेमाल के ही प्रयास हैं।

वर्षा जल संरक्षण का अनूठा शास्त्र

वर्षा जल को बचाने के लिए मरुभूमि के लोगों ने खूब मंथन किया और अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र ही विकसित कर लिया। इस शास्त्र ने जल को तीन रूपों में बांटा है। पहला पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है जिसे नदी, तालाब, बावड़ी आदि में संचित किया जा सकता है। दूसरा पाताल का पानी कहलाता है, जिसे कुएं खोदकर निकाला जाता है। तीसरा पानी पाताल और पालर के बीच का है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा का माप इसी पानी से होता है। जितना अंगुल पानी धरती में समाए, उतनी अंगुल वर्षा मानी जाती है।

सेवा में शामिल जल संरक्षण

राजस्थान में वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका हमेशा बनी रही है। इसी कारण यहां के राजा-महाराजा और सामंतों, जागीरदारों और सेठ-साहूकारों द्वारा सेवा कार्य या पुण्य अर्जन के साधन के रूप में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया।

कुई निर्माता चेजारों का सम्मान

राजस्थान में कुई निर्माण करने वालों को चेजारा कहा जाता है। इन चेजारों को विशेष दर्जा प्राप्त था। कुई निर्माण के बाद उत्सव मनाते हुए चेजारों को अलग-अलग तरह की भेंट देकर ससम्मान विदा किया जाता था। कुई के बाद भी उनका रिश्ता बना रहता था। तीज, त्योहारों और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में उन्हें निमंत्रण देकर भेंट दी जाती थी। फसल आने पर खलिहान का एक हिस्सा उनके लिए रखा जाता था।

साथी हाथ बढ़ाना की सोच

राजस्थान में आज विद्यमान कई तालाब शताब्दियों पहले ग्राम-बस्तियों के सामूहिक अभिक्रम से खोदे गए थे। उस समय शुरुआत में खोदे जाने पर जो मिट्टी का ढेर आगोर में इकट्ठा किया गया, उसे लाखेटा कहा जाता है। इनके जल क्षेत्र में आई मिट्टी नियमित रूप से गांव के श्रमदान से निकाली जाती थी, जिसमें महिलाओं की भूमिका विशेष महत्त्व रखती थी। आज भी महिलाएं प्रत्येक अमावस्या और नवरात्र में नाड़ी से मिट्टी निकालती हैं।

तालाब की सुरक्षा के सख्त नियम

जलाशयों को सुरक्षित रखने, मिट्टी का कटाव रोकने तथा पेयजल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वहां पशुओं का चरना, मनुष्यों का शौच जाना, पशुओं या मनुष्यों को तालाब मे स्नान करना, आदि पर पाबंदी थी। यह आज भी विद्यमान है। सामान्यतया तालाबों पर धार्मिक स्थलों और पवित्र माने जाने वाले पेड़ों को विकसित किया गया। धर्म के नाम पर शुद्धता और स्वच्छता को जोड़कर कुछ परंपराएं बनाई गईं, जिनमें पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध और गंदगी फैलाने पर आर्थिक दंड अथवा सामाजिक बहिष्कार जैसे उपाय किए गए।

कलसी में भरा नीर

गांव के लोग नाड़ी से निकालकर पानी को कलसी या पखाल में भरकर घरों तक ले जाते थे। कलसी एक बड़ा मिट्टी का घड़ा होता था तथा पखाल चमड़े से बना थैला होता था। समय बीतने के साथ धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पखाल का प्रचलन खत्म हो चला है लेकिन कलसी का उपयोग मुख्यतः गर्मी के दिनों में बहुत उपयोगी है। गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। कलसी का एक फायदा यह भी है कि गांव के लोग गर्मी के दिनों में पानी को दूर से भरकर लाते हैं तो तेज धूप होने के बावजूद इसमें पानी गर्म नहीं होता है जबकि धातु के बर्तन में पानी गर्म हो जाता है। रेगिस्तान में पौधों को जीवित रखना भी एक तपस्या से कम नहीं। प्रतिदिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुछ किसान बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिट्टी के घड़ों में छेदकर इसे जमीन में गाड़ देते हैं व पानी भर देते हैं।

मिल-जुलकर खोदे गए खड़ीन

खड़ीन का निर्माण सामान्यतः खरीफ या रबी की फसल कटने के बाद दिसंबर और जून में किया जाता था, क्योंकि इस दौरान किसानों के पास अतिरिक्त समय होता है। खड़ीन मिट्टी का एक बांध है, जिसे सामूहिक प्रयासों से किसी ढलान वाली जगह के नीचे बनाया जाता, जिससे ढलान पर गिरकर नीचे आने (बहने) वाला पानी रुक सके। खड़ीन से जमीन की नमी बढ़ने के साथ-साथ बहकर आने वाली खाद एवं मिट्टी से उर्वरकता में भी वृद्धि होती है। नमी की मात्रा बढ़ने से एक वर्ष में दो फसलें लेना भी संभव हो जाता है।

पन्ना मीना बावड़ी, आमेर, जयपुर

बावड़ी निजी लेकिन पानी सबका

राजस्थान के सभी समुदायों में बावड़ी बनवाने का कार्य हमेशा ही केंद्रीय स्थान पर रहा है। यहां निजी तौर पर बनाई जाने वाली बावड़ियां भी सामुदायिक उपयोग के लिए खुली थीं। सहयोग व भाईचारे की भावना जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए कुओं, जलाशयों तथा बावड़ियों को खुदवाना एक परोपकारी गतिविधि रही है। •

डिग्गी निर्माण

नहरी जल का संरक्षण और कुशलतम उपयोग

राजस्थान, जहां वर्षा न्यूनाधिक रूप में और उसकी मात्रा अनिश्चित है तथा राज्य के आधे से अधिक भाग पर मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय शुष्क दशाएं प्रभावी हैं, ऐसे में यहां सिंचाई का सर्वाधिक महत्व है। राज्य में नदियों से नहरें निकालकर तथा निकटवर्ती राज्यों की नदियों का जल नहरों के माध्यम से सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। नहरी जल के संरक्षण एवं इसके कुशलतम उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डिग्गी निर्माण आदि पर अनुदान देकर कृषकों को संबल दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 40 फीसदी लघु व सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। डिग्गी निर्माण पर देय अनुदान राशि लघु एवं सीमांत कृषक के लिए लागत का 85 फीसदी या अधिकतम राशि 3 लाख 40 हजार रुपये जो भी कम हो राज्य सरकार द्वारा देय है। अन्य कृषकों के लिए लागत का 75 फीसदी या अधिकतम राशि 3 लाख रुपये जो भी कम हो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में भी सिंचाई के जल की उपलब्धता एवं सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने संबंधी घोषणा की गई है।

नहरी क्षेत्र के कृषक जहां सिंचाई बारी स्वीकृत हो, अनुदान के पात्र होंगे। जो कृषक सिंचित क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट आवंटी, गैर खातेदार हैं, वे अनुदान के पात्र होंगे। आवेदनकर्ता कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। डिग्गी निर्माण के साथ स्प्रिंकलर/ ड्रिप/ माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित किया जाना जरूरी होगा। डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में अनुदान से लाभान्वित कृषक दोबारा डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान के पात्र नहीं होंगे। •

मोहित जैन
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

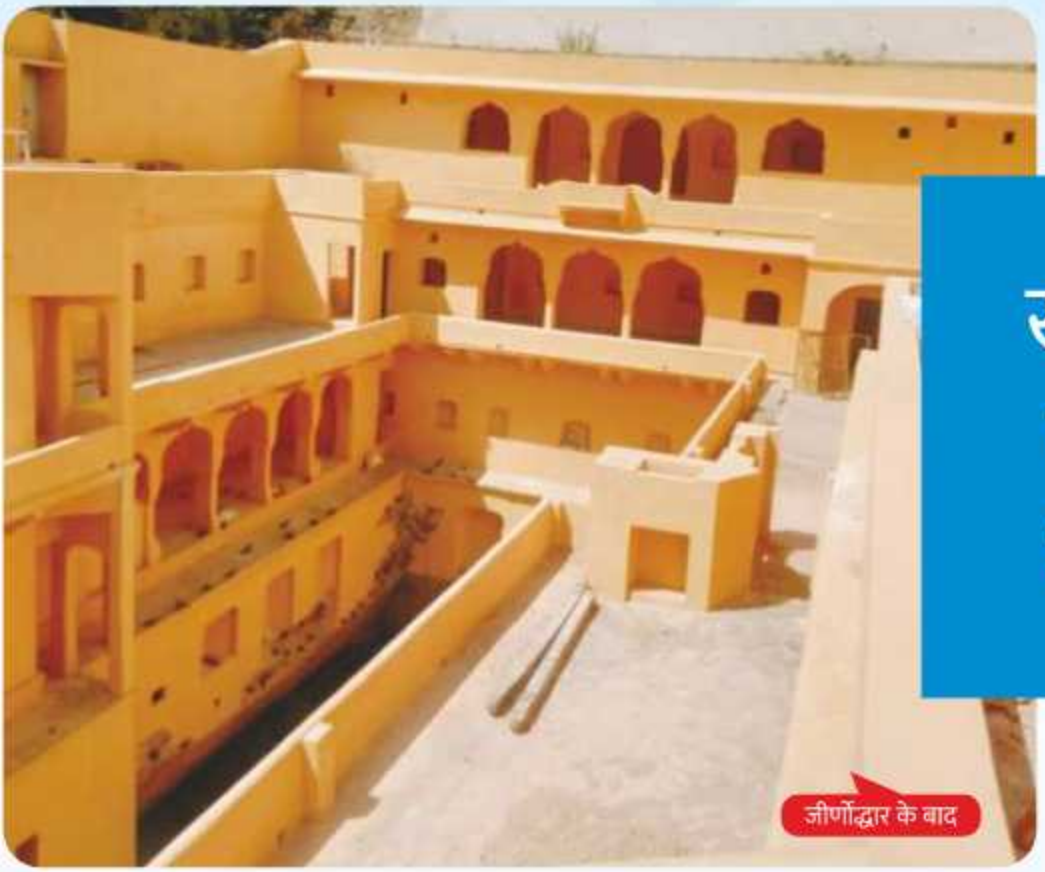

खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार

किशन लाल मीना
अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

खानिया की बावड़ी चूलगिरी जैन मंदिर के सामने घाट की गुणी आगरा रोड पर स्थित है, खानिया बावड़ी का निर्माण ज्येष्ठ माह एकादशी सम्वत 1899 में महाराजा जगत सिंह द्वारा शुद्ध पानी हेतु कराया गया था। यह बावड़ी चार मंजिल की है जिसमें पानी आने का स्रोत पहाड़ी के गुप्त झरने हैं। इसमें एक शिव मंदिर भी बना हुआ है जहां काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना (IRGY-Urban) कार्य योजना के तहत इस बावड़ी की मरम्मत, रंगरोगन एवं डिसिल्टिंग का कार्य किया गया।

खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार उपरान्त लोगों को शुद्ध जल, पर्यटन को प्रोत्साहन एवं ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण मिला। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना का राजस्थान में प्रारम्भ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक सितम्बर, 2022 को जयपुर शहर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से किया गया तथा उसी दिन मुख्यमंत्री द्वारा खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारम्भ एवं शिलान्यास किया गया। यह कार्य 31 मार्च, 2023 को पूर्ण किया जा चुका है जिसमें कुल 18.49 लाख रुपये व्यय हुए है एवं इस कार्य से 854 मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। वर्तमान में खानिया की बावड़ी एवं जग्गा की बावड़ी का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हो चुका है।

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर को बचाया गया है। जीर्णोद्धार होने के उपरान्त चार मंजिला बावड़ी अब आकर्षण का केन्द्र बन चुकी है। •

महंगाई राहत

शिविर में 10 योजनाओं की मिल रही

गारंटी

श्याम सुंदर शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने प्रदेश के गरीब व्यक्ति के साथ-साथ युवाओं किसानों और महिला वर्ग का हमेशा ध्यान रखा। उनके उत्थान और कल्याण के लिए समय-समय पर योजनाएं बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वर्ष 2023-2024 का बजट निश्चित तौर पर गरीब के उत्थान के साथ-साथ किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विभिन्न नवाचार करके उनके कल्याण के लिए योजनाएं लाकर उनके दुख-दर्द में सहयोगी बन रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर मंथन किया और सुझावों के साथ इन्हें लागू करने के लिए पूरे प्रदेश में शहर और गांव में महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों तक इसका लाभ सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने का निर्णय किया। बजट के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्य सचिव तथा आला अफसरों से विभिन्न स्तर पर बैठक कर तय किया गया कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर शुरू किए जाएं और 30 जून तक इन्हें लगाकर प्रदेशवासियों को उनके निवास के पास ही रजिस्ट्रेशन का काम किया जाए। यह काम निश्चित तौर पर चुनौती भरा जरूर था, लेकिन पूरे प्रदेश में 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर लगाने शुरू किए गए। इसी बीच सरकारी मंत्रालय कर्मचारियों के साथ ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर शिविर में भाग नहीं लेने का निर्णय कर लिया और वे हड़ताल पर चले गए। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए समय

पर महंगाई राहत शिविर लगाने के फैसले को यथावत जारी रखा।

शुरुआती दौर में इस बात की चुनौती बनी हुई थी कि शिविर कैसे सफल होंगे लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास और सूझबूझ के कारण ही 24 अप्रैल को जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के महापुरा ग्राम पंचायत से इस महंगाई राहत शिविर की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। इस शानदार शुरुआत के पहले ही दिन से आम लोगों और जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिला। इसी के चलते पहले दिन ही जो सफलता मिली उससे लगने लगा कि अब 10 योजनाओं की गारंटी का यह सफर निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ-साथ किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए उपयोगी होता नजर आया। मुख्यमंत्री के साथ ही पूरे प्रदेश भर में प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर महंगाई राहत शिविर शुरू किए।

मुख्यमंत्री का यह नया प्रयोग निश्चित तौर पर लोगों को आश्चर्य लग रहा था लेकिन जैसे-जैसे महंगाई राहत शिविर के माध्यम से लोगों को राहत मिलना शुरू हुई कि महंगाई राहत शिविरों में लोगों के आने का सिलसिला तेजी से बढ़ता गया। प्रदेश में करोड़ों लोगों का पंजीयन विभिन्न योजनाओं में किया जा चुका है और एक करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो चुका है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए गए हैं।

महंगाई राहत शिविर में इस बार राजीव गांधी मित्रों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों को भी तैनात किया गया। इससे आने वाले आमजन को इलाज की सुविधा भी प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ कई जिलों के गांव में महंगाई राहत शिविरों में जाकर वहां लोगों से फीडबैक ले चुके हैं। शिविर लगाने से असली लाभार्थी को इसका लाभ मिलना आसान हो गया है।

यह पहली बार है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जो उसका हकदार है। जनाधार से जोड़कर योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करने से 100 यूनिट बिजली का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-2024 में 10 योजनाओं के माध्यम से जरुरतमंदों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को महंगाई राहत शिविर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लाभ दिया जा रहा है। •

महंगाई राहत कैंप

हर वर्ग को मिल रहा संबल
संवर रही जिंदगी

सुधाकर सोनी
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

महंगाई वर्तमान दौर की वह समस्या है जिससे आम आदमी सबसे ज्यादा त्रस्त है। आर्थिक तंगी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लोककल्याणकारी सरकारों का यह दायित्व है कि दिन-रात बढ़ती महंगाई से जनता को राहत दिलाए। आम आदमी की इसी पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरोकार निभाते हुए संवेदनशील पहल की है। आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई जनउपयोगी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में पात्र लोगों को राज्य सरकार की 10 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक साथ मौके पर ही दिया जा रहा है। आसान प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर महंगाई से तत्काल राहत दी जा रही है। इस तरह के कैंपों का आयोजन कर हर वर्ग को महंगाई से राहत देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद प्रत्येक परिवार के मासिक खर्च में बचत हो रही है। एक महीने से भी कम वक्त में राज्य के एक करोड़ से अधिक परिवारों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त करना इन कैंपों की सफलता का प्रमाण है। इस अल्प अवधि में कैंपों में 4.50 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्डों का वितरण किया जा चुका है। ये कैंप आमजन की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाले साबित हो रहे हैं। खासतौर से समाज के वंचित और असहाय वर्ग के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं हैं। प्रदेश भर से सामने आ रहे लोगों के अनुभव इन कैंपों की कामयाबी की कहानी स्वत: ही बयां कर रहे हैं।

सुमन के परिवार को मिला संबल

सीकर जिले के बारी गांव की सुमन देवी के परिवार पर वज्रपात ही हो गया जब विदेश में उनके पति की हृदयाघात के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई। सुमन के सास-ससुर पहले से ही पक्षाघात से पीड़ित थे। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। दो छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी सुमन पर आ गई। अधिकारियों को पता चलने पर प्री-कैंप के दौरान ही सुमन देवी की एकल नारी पेंशन का आवेदन करवाकर स्वीकृति जारी की गई। कैंप के दौरान अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर पालनहार योजना में आवेदन करवाया तथा स्वीकृति जारी की। कैंप में उन्हें 100 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि तथा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के गारंटी कार्ड सौंपे गए। इन योजनाओं के लाभ से सुमन के परिवार को संबल मिला है और परेशानियां काफी हद तक कम हो गई हैं।

सरोज को मिला जीवन का सहारा

कोटा जिले के खंड गावड़ी में रहने वाली सरोज के पति की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। सरोज का बेटा विमंदित है और उसके पास पेंशन के अलावा निश्चित आय का अन्य कोई साधन नहीं है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने सरोज के जीवन की मुश्किलें और बढ़ा दीं। लेकिन राज्य सरकार की पहल से सरोज के जीवन में उम्मीद जगी है। महंगाई राहत कैंप में सरोज को एक साथ 5 योजनाओं के लाभ की गारंटी मिली। सरोज का कहना है कि पेंशन की बढ़ी हुई राशि, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से उसे महंगाई से राहत मिलेगी और वह अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी पाएगी। सरोज राज्य सरकार का बार-बार आभार व्यक्त करती है।

कुवैत जाकर सबको महंगाई राहत कैंप के बारे में बताऊंगा

डूंगरपुर के छात्र भव्य पाटीदार दीनदयाल ऑडिटोरियम में चल रहे महंगाई

राहत कैंप में पहुंचे। यहां जन आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज दिखाने पर उनके परिवार का 7 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कर उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे गये। भव्य के पिता विक्रांत पाटीदार कुवैत में मजदूरी करते हैं और इन दिनों डूंगरपुर आए हुए हैं। जब भव्य ने अपने पिता को सातों योजनाओं के मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिखाए तो एकबारगी उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा- "डेढ़-दो साल बाद यहां आया हूं। बहुत कुछ बदल गया है। राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कुवैत लौटकर वहां हमारे क्षेत्र के लोगों को महंगाई राहत कैंप के बारे में बताऊंगा।"

सस्ते गैस सिलेंडर से हेमलता के चेहरे पर छलकी खुशी

कोटा के संत कबीर पार्क में लगे कैंप में आई दिव्यांग हेमलता का सस्ते गैस सिलेंडर के लिए पंजीकरण हुआ तो वह मारे खुशी के ताली बजाकर प्रसन्नता का इजहार करने लगी और सरकार का यह सुविधा देने पर बार-बार आभार जताया। बापू बस्ती निवासी हेमलता ने बताया कि वह और उसके पति दोनों दिव्यांग हैं तथा मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ऐसे में सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडर की सुविधा देकर बहुत अच्छा काम किया है। सिलेंडर के जो पैसे बचेंगे उनसे घर का और खर्चा चलेगा। इसी प्रकार नयापुरा निवासी कुंज बिहारी बैरवा पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करते हैं ताकि वह महंगाई के दौर में अपने पिता की घर चलाने में मदद कर सकें। कुंज बिहारी महीने के 7,500 रुपये कमाते हैं जिसमें उन्हें घर के खर्चों के साथ-साथ ईएमआई भी देनी पड़ती है। उनका कहना है कि महंगाई राहत कैंप में अब उन्हें 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, वहीं 100 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

प्रतिकूल परिस्थितियों में मिला सरकार का सहारा

श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ गांव में आयोजित कैंप में पहुंची 90 वर्षीय वृद्धा मनोहरी ने बताया कि उसके तीन पुत्र हैं, जिनमें से 2 का देहांत हो चुका है तथा एक पुत्र मजदूरी कर परिवार पाल रहा है। ऐसे में महंगाई राहत कैंप के माध्यम से सरकार की पांच योजनाओं का लाभ मिलने से परिवार को बड़ा सहारा मिलेगा। मनोहरी देवी ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, निशुल्क बिजली योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के गारंटी कार्ड प्राप्त कर राज्य सरकार को दिल से दुआएं दीं।

शारदा को मिला सरकार का साथ

अजमेर जिले की बिजयनगर निवासी शारदा कम उम्र में ही पति को खो चुकी थी। एक बेटा भी दुर्घटना का शिकार हो गया। शारदा पर अपनी दो बेटियों को पालने की जिम्मेदारी है। राहत कैंप में उम्मीद लेकर आई शारदा का पांच योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हुआ। राहत मिलते ही उसकी निराश आंखों में चमक लौट आई। शारदा ने कहा कि उस जैसी महिलाओं के जीवन में रोशनी लाकर यह अभियान अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है।

सरकार ने बढ़ाए मदद को हाथ

करंट से हादसे का शिकार होने के बाद चूरू जिले के दीनदयाल को अपने दोनों हाथ खोने पड़े। मुश्किलों भरी उसकी जिंदगी में महंगाई राहत कैंप वरदान साबित हुआ। कैंप में उसका 6 योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ जिससे अब उसे बढ़ी हुई पेंशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और परिवार को अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। उसने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे में उसके हाथ चले गए, लेकिन सरकार की योजनाओं का साथ मिला है। इन योजनाओं से मुश्किलें कम होंगी और महंगाई से जूझते परिवार को राहत मिलेगी।

प्रेम बाई को मिली चूल्हे के धुएं से मुक्ति

झालावाड़ जिले की खेड़ा ग्राम पंचायत निवासी प्रेम बाई महंगा गैस सिलेंडर न खरीद पाने के कारण अब तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। लेकिन अब महज 500 रुपये में सिलेंडर मिलने से वह गैस चूल्हे पर खाना पका पाएगी। महंगाई राहत कैंप प्रेम बाई के लिए चूल्हे के धुएं से मुक्ति की सौगात लेकर आया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के साथ ही उन्हें 7 अन्य योजनाओं का लाभ भी मिला है जो उन्हें बेतहाशा बढ़ती महंगाई से राहत देगा। प्रेम बाई कहती हैं कि इन योजनाओं के लाभ से उनका आर्थिक बोझ कम होगा और राज्य सरकार की यह पहल बड़ी राहत देने वाली है।

अक्षत को अब घर के पास ही मिलेगा रोजगार

जयपुर की आजाद नगर कच्ची बस्ती निवासी 28 साल के अक्षत देव कोरोना काल में बेरोजगार हो गए थे। बहुत तलाश के बाद भी दोबारा काम नहीं मिला। पड़ोसियों से जानकारी मिली तो घाट की गुणी टनल के पास आयोजित महंगाई राहत कैंप में पहुंचे। बीपीएल कार्ड धारक अक्षत को कुछ ही मिनटों में 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के गारंटी कार्ड मिल गए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए अक्षत कहते हैं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना से अब उन्हें घर के पास ही 125 दिनों का रोजगार मिल जाएगा। साथ ही, अन्य योजनाओं का लाभ मिलने से महंगाई के दौर में घर चलाने में काफी मदद मिलेगी।

दिव्यांग दंपती का सहारा बनी राज्य सरकार

जिंदगी के सफर में शारीरिक अक्षमता कदम -कदम पर चुनौतियां खड़ी करती है और यदि हमसफर भी निशक्त हो तो दुश्वारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही विपरीत हालात का सामना कर रहे थे बाड़मेर निवासी दिव्यांग राजूराम और उनकी दृष्टिहीन पत्नी। राहत की आस लिए राजूराम जब महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे तो कैंप प्रभारी ने उनकी सहायता करते हुए तुरंत छह योजनाओं से लाभान्वित कर गारंटी कार्ड प्रदान किए।

राजूराम ने बताया कि 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 1,000 रुपये मासिक पेंशन तथा 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलने से उनके परिवार को बड़ा संबल मिला है। राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राजूराम की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।

लोगों के फर्श चमकाने वाली गुड्डी की चमकी जिंदगी

बूंदी शहर के आजाद पार्क में आयोजित कैंप में 42 वर्षीय गुड्डी बाई को जब एक साथ 6 योजनाओं के गारंटी कार्ड मिले तो उनका चेहरा खिल उठा। प्रतिकूल हालातों से जूझ रही गुड्डी 6 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में अपने पति को गंवा चुकी है। अपने दो बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी गुड्डी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दूसरों के घरों में झाड़ू-पोंछा कर वह अपना परिवार पालती है।

कैंप में गुड्डी बाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के गारंटी कार्ड मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलीं- "बढ़ती महंगाई के चलते बच्चों के भविष्य की चिंता सताती थी, लेकिन अब परिवार पालना पहले से आसान होगा।"

मुश्किल समय में मिला सरकार का साथ

बीकानेर निवासी 52 वर्षीय गीता देवी का जीवन मुश्किलों से भरा है। पति की मृत्यु हो जाने से 4 संतानों की वह अकेली पालनहार हैं। घर-परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए वे पापड़ बनाने का कार्य करती हैं, लेकिन आय अधिक नहीं होने से आर्थिक संकट बना रहता है। महंगाई राहत कैंप में पहुंची तो उन्हें तुरंत राहत देने वाली 7 योजनाओं का लाभ मिला। राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए गीता देवी कहती हैं कि मुश्किल समय में राज्य सरकार ने सहायता का हाथ बढ़ाया। अब उन्हें हर महीने बढ़ी हुई पेंशन, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ ही स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और रोजगार की गारंटी मिल गई है। मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद।

मध्यम वर्ग के लिए महंगाई से राहत भी, बचत भी

महंगाई राहत कैंप अल्प आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आए हैं। जयपुर निवासी श्रीमती शालू सोनी एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। शालू कहती हैं कि अच्छे पद और वेतन के बावजूद उनका परिवार भी महंगाई की मार से अछूता नहीं है।

महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद शालू ने बताया कि 100 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य

बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल जाएगा। साथ ही 10 लाख के दुर्घटना बीमा का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। शालू कहती हैं कि मध्यम वर्ग पर अक्सर करों का बोझ ही डाला जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों की परेशानी को कम करने का काम किया है जो कि स्वागत योग्य कदम है।

सरस्वती के लिए पति का इलाज करवाना होगा आसान

श्रीगंगानगर जिले की रावलामंडी निवासी सरस्वती को कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना का लाभ मिला।

गारंटी कार्ड पाकर खुश सरस्वती ने बताया कि गरीब परिवार में मुश्किल से ही गुजर-बसर होता है। ऐसे में सरकार की इन योजनाओं से बड़ी राहत मिलेगी। चिरंजीवी योजना के माध्यम से अब वे पति के गुर्दे की बीमारी का इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगी।

एरा मौका कदै-कदै आवे

सिरोही जिले की चनार ग्राम पंचायत में श्रीमती चंदा गाडोलिया लोहार को जब भौंपू पर हो रहे प्रचार के जरिये पता चला कि महंगाई राहत कैंप का आयोजन हो रहा है तो वह तत्काल कैंप में पहुंची। उसने अधिकारियों को बताया कि उसके 4 बच्चे हैं और वृद्ध सास-ससुर की जिम्मेदारी भी उस पर ही है। महंगाई में जीना मुश्किल है। इसके बाद श्रीमती चंदा देवी का कैंप में सात योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कर लाभान्वित किया गया। इस पर श्रीमती चंदा के वृद्ध ससुर श्री छोगाराम ने कहा-"एरा मौका कदै-कदै आवे, भगवान सरकार रो भलो करज्यो।" •

महंगाई राहत कैंप की अहम कड़ी राजीव गांधी युवा मित्र

सविता सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राज्य सरकार की हमेशा से ही यह मंशा रही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र एवं प्रभावी रूप से पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021 -22 के राज्य बजट की घोषणा के बाद राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का संचालन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत युवाओं की ऐसी सशक्त टीम बनाई गई है, जो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर आमजन से संवाद कर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से परिचित करवाती है।

गांव-गांव और गली-गली, देखो एक है लहर चली
जन जागरूक करने को, युवा शक्ति साथ चली।

यह कार्यक्रम राज्य के कर्मठ एवं होनहार युवाओं के लिए ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से युवाओं को सरकारी कामकाज और आमजन के बीच सामंजस्य निभाने का अवसर मिलता है। साथ ही, युवा मित्र लोगों की वास्तविक समस्याओं से रू-ब-रू होकर उन्हें सुलझाने के लिए सरकार और आमजन के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। महंगाई राहत कैंपों में युवा मित्र राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

राजीव गांधी युवा कोर

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के लिए राजीव गांधी युवा कोर (RYC) का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत राजीव गांधी युवा मित्र समन्वयक (RYMC), राजीव गांधी युवा मित्र (RYM) एवं राजीव गांधी युवा वालंटियर्स (RYV) को शामिल किया गया है।

राजीव गांधी युवा मित्रों द्वारा तीन स्तर पर कार्य किये जाते हैं। प्रत्येक इंटर्न ब्लॉक या निकाय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से जनसंपर्क का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में तकनीक और सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए इंटर्न विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों जैसे वाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर की मदद से आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं। समाज के अंतिम छोर तक सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच हो सके, इसके लिए इंटर्न अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में जाकर आमजन से संवाद स्थापित करते हैं और जमीनी स्तर पर आने वाली उनकी समस्याओं को हल करते हैं।

हित और हक बतलाना है, जन जागृति लाना है,
देखो कोई छूट न जाए, कोई वंचित रह न जाए।

कार्यक्रम की सफल मॉनिटरिंग के लिए आरवाईएमपी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसमें युवा मित्र अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप में निजी नेटवर्क और ग्रुप, इवेंट्स, फील्डवर्क, योजनाएं, प्रशिक्षण वीडियो, कैंपेन अपडेट्स एवं पुरस्कार की सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं।

कार्यक्रम की प्रगति

मार्च, 2023 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,752 राजीव गांधी युवा मित्र कार्यरत हैं। इनमें अजमेर में 51, अलवर में 82, बांसवाड़ा में 57, बारां में 45, बाड़मेर में 87, भरतपुर में 64, भीलवाड़ा में 66, बीकानेर में 49, बूंदी में 35, चित्तौड़गढ़ में 14, चूरू में 44, दौसा में 63, धौलपुर में 28, डूंगरपुर में 31, गंगानगर में 44, हनुमानगढ़ में 32, जयपुर में 280, जैसलमेर में 35, जालोर में 33, झालावाड़ में

31, झुंझुनूं में 55, जोधपुर में 104, करौली में 38, कोटा में 27, नागौर में 77, पाली में 49, प्रतापगढ़ में 31, राजसमंद में 14, सवाई माधोपुर में 35, सीकर में 53, सिरोही में 29, टोंक में 38 और उदयपुर में 33 युवा मित्र कार्य कर रहे हैं। युवा मित्रों के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए इस वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार 2 हजार 500 युवा मित्रों की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय प्रावधान

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 47.07 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान रखा गया है। इस राशि के विरुद्ध 31 मार्च, 2023 तक कुल 36.25 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

जन-संवाद से योजनाओं का प्रचार-प्रसार

राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम राज्य सरकार की अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार लक्षित समूहों तक संभव हो पाया है। इन युवा मित्रों द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण के दौरान परिवारों से संपर्क स्थापित कर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। मार्च, 2023 तक कुल 39 लाख 84 हजार 129 परिवारों से संपर्क कर संवाद स्थापित किया जा चुका है।

कार्यक्रम के अंतर्गत युवा मित्रों के द्वारा जन-संवाद के माध्यम से मार्च, 2023 तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 92 हजार 712, पालनहार योजना में 35 हजार 289, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में 14 हजार 409, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 6 हजार 282, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 4 हजार 904, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में 2 हजार 855 लाभार्थी स्वीकृत कराये जा चुके हैं।

चिरंजीवी हो रहा राजस्थान, महिला की है नई उड़ान
कामकाज अब है आसान, सबके हाथ है जनाधार।

गांधी दर्शन का एक अनूठा प्रयास

यह कार्यक्रम गांधी दर्शन का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें जन-कल्याण, जन-सहभागिता एवं जन-जागरूकता का समावेश है और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा वर्ग, समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से वंचित वर्गों से जुड़कर उनके उत्थान में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और साथ ही युवाओं को गांधी दर्शन को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है।

सबको सम्मान दिलाना है, नारी को सशक्त बनाना है
युवा जोश जगाना है, गांधी दर्शन अब लाना है।

महंगाई राहत कैंप में राहत बांट रहे राजीव गांधी युवा मित्र

राज्य सरकार की ओर से संचालित किए जा रहे महंगाई राहत कैंप जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकें, इसके लिए राजीव गांधी युवा मित्र अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। इन कैंपों में कार्यरत राजीव गांधी युवा मित्र यहां आने वाले लोगों को योजनाओं के बारे में जरूरी जानकारी दे रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में पूरी मदद कर रहे हैं।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का होगा गठन

अरुण कुमार जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं नगर निगम द्वारा सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की। यह बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नवनिर्माण, विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए योजना तैयार करेगा। यह नई पीढ़ी के लिए भी माहौल तैयार करेगा।

श्री गहलोत ने महाराणा प्रताप की समाधि, राजतिलक स्थली और अन्य स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराने और मीरा मेदपाट बालिका छात्रावास के समीप की भूमि को छात्रावास के लिए आवंटित करने की भी घोषणा की। चावंड में 4 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की जा चुकी है जिसके कार्यादेश जारी कर दिए हैं।

अब हर जिले में दो लवकुश वाटिकाएं

प्रदेश के सभी जिलों में लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाटिकाओं के लिए 66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

श्री गहलोत के निर्णय से इन वाटिकाओं में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। यहां इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह बनेगी। इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना है।

जोधपुर का 565 वां स्थापना दिवस

शौर्य, पराक्रम, अनुपम लोक संस्कृति और मनोहारी परंपराओं के साथ ही कई विलक्षण थातियों से भरे जोधपुर का 565 वां स्थापना दिवस 12 मई को विभिन्न मनोहारी एवं आकर्षक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए।

जोधपुर स्थापना दिवस की शुरुआत रन फॉर जोधपुर के साथ हुई। इस कार्यक्रम में शहर की विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, बीएसएफ के कैमल कॉन्टिंजेंट आदि ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से स्थापना दिवस दौड़ को सांस्कृतिक रस-रंगों से भर दिया।

जोधपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों के समूहों ने लोकवाद्यों की सुमधुर स्वर लहरियों से रंग जमाया। अपनी प्रस्तुतियों से इन लोक कलाकारों ने मरुधरा की लोक संस्कृति के रंगों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। इनका लुत्फ उठाने के लिए देशी-विदेशी पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों का पर्यटक स्थलों पर दिन भर तांता लगा रहा।

इसी श्रृंखला में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने शहर के सरदार राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय मंडोर, उम्मेद उद्यान एवं मंडोर उद्यान आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा। स्कूली बच्चों के लिए उम्मेद उद्यान स्थित सरदार राजकीय संग्रहालय में आपणो जोधाणा विषय पर निबंध

प्रतियोगिता तथा मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 565 वर्ष का जोधपुर आज भी अपनी लोक कला, संस्कृति और खूबसूरती को बरकरार रखे हुए है।

158 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत

संचालन के लिए 1,462 नवीन पद मंजूर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 158 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने, 3 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 नया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही, उन्होंने क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा अधिकारी के 162, नर्स द्वितीय श्रेणी के 324, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के 162, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4, फार्मासिस्ट के 162, लैब टेक्नीशियन के 162, वार्ड ब्वॉय के 324 एवं सफाई कर्मचारी के 162 पदों सहित कुल 1,462 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के मुताबिक सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर, भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, पाली, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनं, जालौर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, चित्तौड़गढ़, करौली, बीकानेर, टोंक एवं प्रतापगढ़ जिलों में विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त भरतपुर के बसई, डूंगरपुर के घाटी मोहल्ला व करौली के काछीपुरा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बाड़मेर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने को मंजूरी दी गई है।

20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज

राज्य सरकार 20 लाख किसानों को निःशुल्क सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराएगी। इस पर राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्गमीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए कोम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ फसल के लिए टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर व बैंगन, रबी फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर व बैंगन तथा जायद फसल के लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी व ग्वार के बीज शामिल हैं।

इसमें खरीफ-2023 के लिए 7 लाख, रबी 2023-24 के लिए 11 लाख एवं जायद-2024 के लिए 2 लाख किट वितरण का लक्ष्य है।

यातायात पुलिस में 500 नए पदों का होगा सृजन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बढ़ते वाहनों के दबाव से सुगम यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस में 500 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से उपनिरीक्षक के 20 पद, हेड कांस्टेबल के 80 पद और कांस्टेबल के 400 पदों सहित कुल 500 पद सृजित होंगे।

प्रदेश के पांच जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यक छात्रावास

धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पांच नए अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से 14 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता रखी गई है। छात्रावासों में रहकर अल्पसंख्यक विद्यार्थी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 मई को केंद्रीय बस स्टैंड, सिंधी कैंप जयपुर पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस अवसर अपने उद्बोधन में उन्होंने महिला यात्रियों के लिए रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। रियायती यात्रा का दायरा बढ़ने से महिलाएं रोडवेज की साधारण बसों के साथ-साथ अब एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई को माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक कला मंडल परिसर में लगाई गई जनजाति विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। जनजाति विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ परंपरा, संस्कृति तथा कला कौशल की रचनात्मकता में आगे लाने के उद्देश्य से कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को अब मिलेगी प्रतिमाह 2,500 रुपये सहायता राशि

राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये पेंशन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, जिन्हें वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है। इसे बढ़ाकर अब 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 मई, 2023 (देय 1 जून, 2023) से मिलेगी।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 8 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से एसएमएस चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से बेहतर इलाज मिल सकेगा।

प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन

महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन की कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रत्येक समिति की अंशदान की 3 लाख रुपये राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिए कुल 10.53 करोड़ रुपये का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रारूप के अनुसार, समिति के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी। न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपये होगी। सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अमानत राशि 75 हजार रुपये होगी। किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियां नहीं होंगी। नई समितियों में फर्नीचर्स एवं अन्य संसाधनों के लिए 50 हजार रुपये प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) से दिए जाएंगे।

1003 करोड़ रुपये से सिंचाई तंत्र होगा मजबूत

राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 1003.19 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से डूंगरपुर जिले में मारगिया लघु सिंचाई परियोजना के तहत बांध एवं नहर का सुदृढ़ीकरण, भीलवाड़ा में मेजा बांध की मुख्य नहरों, बांसवाड़ा में अनास नदी पर साग डूंगरी एनिकट, थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण, कागदी पिकअपवियर के डाउन स्ट्रिप एक्सेस चैनल की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण, झालावाड़ में आहू नदी पर एनिकट व कॉजवे, कंठाली नदी के कटाव को रोकना, चित्तौड़गढ़ में बड़ी, मानसरोवर व भावलिया बांध के अधिशेष जल से 7.50 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण, बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी पर बैंक प्रोटेक्शन कार्य होंगे।

इसके अलावा बारां के अटरू शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बुधसागर तालाब डाइवर्जन चैनल व मांडपुर लिफ्ट परियोजना के एनिकट से सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई, प्रतापगढ़ में देवद कराडिया लघु सिंचाई परियोजना, कोटा की अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना की शेष रही कच्ची नहर की लाइनिंग व जीर्णोद्धार, सवाईमाधोपुर के भूखा में बनास नदी पर एनिकट, उदयपुर में जावर एनिकट पर निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य होंगे।

साथ ही, जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलोदी लिफ्ट) के 10 हजार हेक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में विभिन्न सिविल एवं मैकेनिकल कार्य तथा स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का विद्युतीकरण कराया जाएगा। इस कार्य में कुल 100 करोड़ रुपये लागत आएगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ व्यय होंगे।

सिकराय नगरपालिका और पापड़दा तहसील बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 मई को दौसा के गीजगढ़ में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के साथ जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां सिकराय को नगरपालिका तथा पापड़दा को उप तहसील से तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की।

बीकानेर के कपिल सरोवर और बूंदी की रामसागर झील का होगा सौंदर्यीकरण

बीकानेर के श्रीकोलायत स्थित कपिल सरोवर और बूंदी के हिंडौली स्थित रामसागर झील का स्वरूप निखरेगा। राज्य सरकार दोनों स्थलों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराएगी। इससे यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, कपिल सरोवर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बूंदी की रामसागर झील के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ साइकिल ट्रैक एवं पार्क का निर्माण भी होगा। इसमें 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इंदिरा गांधी मुख्य नहर के सुधार कार्यों पर खर्च होंगे 40 करोड़ रुपये

राज्य सरकार इंदिरा गांधी मुख्य नहर से निकलने वाली सीधी नहरों और वितरिकाओं को सुदृढ़ कराएगी। इसमें 40 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

योजना के तहत जैसलमेर जिले में नहर की बुर्जी 1254 से 1458.5 के मध्य से निकलने वाली नहरों और वितरिकाओं में सुधार कार्य होंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ रुपये से विभिन्न कार्य होंगे।

प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने तथा इसका संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नहर विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

खेल स्टेडियम, परिसर, अकादमियों एवं मल्टीपरपज इनडोर हॉल के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये मंजूर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस राशि से विभिन्न जिलों में खेल स्टेडियम, खेल परिसर, खेल अकादमियों एवं मल्टीपर्पज इनडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा।

श्री गहलोत के इस निर्णय से खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा तथा वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार कर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे।

इन जिलों में होंगी अकादमियां संचालित : प्रदेश के सातों संभागों में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल शुरू होंगे। वहीं, प्रतापगढ़ में अरनोद, अलवर में कठूमर, थानागाजी, कोटकासिम (किशनगढ़ बास), बांसवाड़ा में कुशलगढ़, बारां में अटरू, बूंदी में देई (हिंडौली), भरतपुर में नदबई, चूरू में सरदारशहर, दौसा में मंडावर (महुवा), धौलपुर में राजाखेड़ा, जयपुर में जमवारामगढ़, झुंझुनूं में मलसीसर (मंडावा), जोधपुर में बिलाड़ा, पीपाड़, बलेसर, नागौर में डेगाना, लाडनूं, पाली में जैतारण, सुमेरपुर, सवाई माधोपुर में बाटोदा (बामनवास), सीकर में दांतारामगढ़, जालौर में रानीवाड़ा, डूंगरपुर में झोंथरीपाल, बाड़मेर में सिवाना में खेल मैदान और अकादमियां संचालित की जाएंगी।

जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ, फ्लड लाइट सहित अत्याधुनिक सुविधाओं का होगा विकास : जयपुर के चौगान स्टेडियम का 12 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार होगा। भरतपुर में 7 करोड़ रुपये से स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जोधपुर में 8.68 करोड़ रुपये से ऑल वैदर स्वीमिंग पूल का निर्माण और 8 करोड़ रुपये से अमृत लाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बारां के शाहबाद में 10 करोड़ रुपये से खेल स्टेडियम तथा खेल छात्रावास का निर्माण होगा। राजसमंद के सरदारपुरा (नाथद्वारा) में 26.02 करोड़ रुपये से कुश्ती अकादमी एवं खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। साथ ही, बीकानेर की सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में 3 करोड़ रुपये की लागत से शूटिंग व तीरंदाजी की सुविधाएं बढ़ेंगी।

नागौर (डीडवाना) में कबड्डी, सीकर (कोलिड़ा), बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइक्लिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, चूरू (राजगढ़) में एथलेटिक्स, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमियां शुरू होंगी। सीकर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनेगा। चूरू, जैसलमेर, धौलपुर, जालौर, नागौर में मल्टीपरपज इनडोर हॉल का निर्माण होगा।

जयपुर के रोजदा, कंवर का बास, जोधपुर के लूणी, अलवर के चांदोली, बाड़मेर के चौहटन, चूरू के सुजानगढ़, तारानगर व सालासर, भरतपुर के भुसावर, डूंगरपुर के सांगवाड़ा, धौलपुर के मनियां, झुंझुनूं के अलसीसर व परसरामपुरा, टोंक के देवली, उदयपुर के जसवंतगढ़ (गोगुंदा), राजसमंद के सरदारपुरा, सवाई माधोपुर के बौंली व गंगापुरसिटी, सिरोही के शिवगंज, श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर,

सादुलशहर और प्रतापगढ़ में खेल स्टेडियम निर्माण और विकास कार्य होंगे। चूरू और पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल शुरू होंगे। सिरोही (माउंट आबू) में पोलो ग्राउंड और उदयपुर में पोलो ग्राउंड एवं डबल ट्रैप रेंज के कार्य होंगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ और नेछवा के राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण होगा। जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ, फ्लड लाइट, पैवेलियन, सिटिंग चेयर आदि अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास होगा।

वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने सिटी पार्क को बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी के लिए किया चयनित

वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्टों का चयन बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में करते हुए मलेशिया के पूलमैन क्वालालमपुर में बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया है।

जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर उदयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया।

जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत से उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में एक प्रमुख इकोटूरिज्म साइट का विकास होगा तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जयसमंद अभयारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किए गए प्रयासों से वर्तमान में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है। राजस्थान में तीन टाइगर सफारी है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बनेंगे 5 नए छात्रावास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नवीन छात्रावास खोलने की मंजूरी दी है। इससे दौसा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं टोंक में छात्रावास खोले जाएंगे।

इनमें दौसा के बहरावंडा में सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, बीकानेर के दामोलाई, जोधपुर के औसियां, जैसलमेर के फलसुंड, टोंक के उनियारा में डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी छात्रावासों के संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 के 5 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। प्रत्येक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता होगी।

हकत्याग के दस्तावेजों का भी होगा प्रशासन गांवों के संग शिविरों में पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के दौरान आयोजित शिविरों में हकत्याग के दस्तावेजों का शिविर स्थल पर ही पंजीयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, जिन पंजीयन उप-जिलों में पूर्णकालीन उप-पंजीयक नियुक्त हैं, उन उप-जिलों में पदस्थापित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को ऐसे उप-जिलों के लिए प्रशासन गांवों से संग अभियान-2023 के दौरान शिविर स्थल पर हकत्याग के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 एवं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल

जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित दस दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 व तीन दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल में जयपुरवासियों ने 2.10 करोड़ रुपये से अधिक के मसालों की खरीद की। 28 अप्रैल से प्रारंभ हुआ मसाला मेला 7 मई को सम्पन्न हुआ। सहकार मसाला मेले में सर्वाधिक बिक्री के लिए अन्य प्रदेशों में केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन, शीर्ष संस्थाओं में प्रथम कॉनफैड व द्वितीय स्थान पर तिलम संघ रहा। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम मथानिया, दूसरा नागौर एवं तीसरा स्थान किशनगढ़ का रहा। इसी तरह से जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर व जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 5 से 7 मई, 2023 तक आर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा पहली बार यह आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 50 स्टॉल्स लगाई गई जिन पर आर्गेनिक उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई।

मुख्यमंत्री ने उदयपुर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई को गोवर्धन विलास स्थित उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने गत 4 वर्षों में गौशालाओं को 2,313 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालकों के दो दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपये का बीमा किया जा रहा है। हर पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोली जा रही हैं। साथ ही, 5 हजार डेयरी बूथ खोले जा रहे हैं, जिससे आमजन को रोजगार मिलेगा। पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, अभी तक 1 हजार 110 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। गौशालाओं को अब 9 माह अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत भी विद्यालयों में बच्चों को अब 6 दिन दूध पिलाया जाएगा।

जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर-19 में किया जाएगा। श्री गहलोत ने राज्य कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस स्थायी पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 25 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा।

प्रदेश में 6 छात्रावास भवनों का होगा निर्माण

घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के निर्माण के साथ उनमें सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक-बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 16.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इससे ब्यावर (अजमेर), भवानी मंडी (झालावाड़), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) और प्रतापगढ़ में सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भवन, कल्याणपुर (बाड़मेर) और श्रीगंगानगर में डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के भवन तैयार होंगे।

छात्रावासों में बढ़ेंगी सुविधाएं : मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू, मिरासी व भिश्ती समुदाय के 299 छात्रावासों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 8.38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे छात्रावासों में स्टडी टेबल मय कुर्सी, बुक रैक, अलमारी, बेड रिप्लेसमेंट, इलैक्ट्रिक गीजर, पंखे एवं लाइट्स, रसोई के बर्तन, पानी की टंकी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को बाल गोपाल योजना में प्रतिदिन दूध

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी नए शैक्षणिक सत्र से रोजाना दूध पीएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।

वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध पिलाया जा रहा है। यह अब शेष चार दिन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अजमेर के सिलोरी में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना

पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा (किशनगढ़) में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक ने स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर एवं वरिष्ठ सहायक के एक-एक पद, उपनिरीक्षक सीपी एवं प्लाटून कमांडर के 2-2 पद, हेड कांस्टेबल के 10 पद तथा कांस्टेबल के 18 (कुल 38) नवीन पदों का सृजन होगा। इसके अलावा व्याख्याता, प्लाटून कमांडर, बारबर, स्वीपर, कुक और हेड कांस्टेबल के कुल 15 पदों पर सेवानिवृत्त अथवा जॉब बेसिस के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी।

श्री गहलोत ने यहां विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 4.34 करोड़ रुपये, उपकरणों के लिए 4.05 लाख रुपये और वाहनों के लिए 29.20 लाख रुपये व्यय करने की भी मंजूरी दी है।

अप्रतिम ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति

जयपुर मेट्रो कला दीर्घा

डॉ. बनवारी पारीक 'नवल'
स्वतंत्र लेखक

विश्वविख्यात और देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में अग्रणी गुलाबी नगर जयपुर बुलंदियों का एक और पायदान चढ़ते हुए बेहद लुभावना हो गया, जब मेट्रो कनेक्टिविटी वाला भारत का यह छठा शहर बना। जयपुर मेट्रो ट्रेन का सफर निश्चय ही बड़ी शान एवं सुकून का है। स्टेशनों व कोचों की स्वच्छता, सुंदरता, वातानुकूलित वातावरण, सुरक्षित व सस्ता सफर अत्याकर्षक हैं। साथ ही यह शहर का तीव्रतम परिवहन है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से इस मेट्रो में अनेक विशिष्टताएं आई हैं, जिसमें यहां की कला दीर्घा अन्यतम है।

जयपुर मेट्रो की कला दीर्घा या संग्रहालय (Jaipur Metro Art Gallery) जयपुर मेट्रो का नागरिकों के लिए संकल्पित स्वर्णिम अध्याय है। छोटी चौपड़ के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर फर्स्ट फ्लोर पर छोटी चौपड़ कुंड के बिल्कुल करीब बेहद आकर्षक अंदाज की यह कला दीर्घा स्थित है। करीब 5 करोड़ रुपये में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित यह आर्ट गैलरी जन-जन को बरबस लुभाती है। यह प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 5:30 तक दर्शकों के लिए खुली रहती है। इस विश्वस्तरीय संग्रहालय में राजस्थान की अप्रतिम ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अनमोल विरासत की मूर्तिकला, रागमाला पेंटिंग एवं अन्य बहुमूल्य धरोहर निहार सकते हैं। यहां 7वीं से 16वीं शताब्दी तक की अद्भुत मूर्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश मेट्रो निर्माणार्थ की गई खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। यहां पर खुदाई से प्राप्त आठ

जयपुर मेट्रो कला दीर्घा

प्राचीन गोमुख भी प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही खुदाई में मिले पुरा-महत्व की धरोहरों के अवशेष, तराशे हुए पत्थर, शिलालेख, मिनिएचर पेंटिंग और मूर्तिशिल्प भी सुसज्जित है। यहां जयपुर ही नहीं, राज्य के दूसरे भागों व संग्रहालयों से प्राप्त कलात्मक वस्तुएं भी प्रदर्शित हैं। यहां पर 101 ऑब्जेक्ट्स, 32 रागमाला पेंटिंग तथा तीन सेल्फी प्वॉइंट्स हैं।

विरासत की पुनर्स्थापना और संरक्षण

कला संग्रहालय में थीम के अनुसार जैन गैलरी, मंदिर कलाकृति गैलरी, हिंदू देवी प्रतिमा गैलरी तथा हिंदू देवता प्रतिमा गैलरी-ये चार दीर्घाएं विकसित की गई हैं। जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन की इस पहल से राज्य की विरासत की पुनर्स्थापना और उसका संरक्षण हो सकेगा। जयपुर टूरिस्ट सर्किल के इस एक और आकर्षण से दर्शक भारत के रियासत युग से रू-ब-रू हो सकेंगे। जयपुर मेट्रो की इस कला दीर्घा ने विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अहम जगह बना ली है।

इस अनोखी जगह को देखने के लिए मामूली शुल्क है। इस आर्ट गैलरी के पुरातत्व विभाग की कंपोजिट टिकट में शामिल होने की बहुत संभावना है। इससे यहां दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसा होने पर कंपोजिट टिकिट से आमेर महल, नाहरगढ़ दुर्ग, हवामहल, जंतर-मंतर, ईसरलाट, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिसोदिया बाग तथा विद्याधर बाग इन आठ के बाद यह कला दीर्घा जयपुर के नौवें टूरिस्ट प्लेस के रूप में जुड़ेगी। सुरक्षा व लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से इस गैलरी में मेट्रो पुलिस भी तैनात है। इस अद्भुत कला दीर्घा से गुलाबी नगरी में एक और सौंदर्य मूल्य जुड़ गया। यह गैलरी अनूठी है, क्योंकि देश के अन्य किसी भी मेट्रो ने ऐसी अवधारणा प्रस्तुत नहीं की है।

संगीतमाला और रागमाला का चित्रांकन

जयपुर मेट्रो की आर्ट गैलरी की रागमाला पेंटिंग में राग-रागिनी चित्रमाला या रागों की माला भारतीय संगीत के पारंपरिक स्वरों के प्रभाव, संवेगों तथा भावनाओं को रंगों के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया है। ये सभी चित्रांकन संगीतमाला और रागमाला इन दो साहित्यों पर आधारित हैं। इनमें भारतीय संगीत के छह राग एवं तीस रागिनियों को मनमोहक चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। रागमाला पेंटिंग के विषय में 'रागमाला-द मिसिंग लिंक' पुस्तक के रचयिता व जयपुर के पद्मश्री तिलक गीताई के मुताबिक लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी तथा काला ये प्रकृति व इंद्रधनुष के सात रंग हैं। इन्हीं से सुर सजते हैं। इन्हीं से तैयार चित्रांकन रागमाला पेंटिंग कहलाती है। उनके अनुसार रागमाला पेंटिंग विभिन्न रागों का सचित्र विवरण प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में धुन और जीवन की अभिव्यक्ति अंतर्निहित होती है।

राजस्थान की विशिष्ट मूर्तिकला

इस आर्ट गैलरी में राजस्थान की मूर्तिकला विशिष्ट है। यहां की अधिकांश मूर्तियों व फलकों के निर्माण का आधार पौराणिक प्रसंग प्रतीत होते हैं। मृण्मय कला के रूप में मूर्तिकला का विकास आद्य ऐतिहासिक युग से शुरू होता है। कालीबंगा व रंगमहल से राजस्थान की मृण्मयी मूर्तिकला का विकास माना जाता है। जयपुर मेट्रो की कला दीर्घा में प्रदर्शित 1,000 वर्ष प्राचीन मूर्तियां मूर्तिकला की बेजोड़ अभिव्यक्ति हैं। यहां की देवी प्रतिमा दीर्घा में एक सहस्राब्दी पुरानी सभ्यता में वर्णित लक्ष्मी व उमा देवी प्रदर्शित हैं। साथ ही इसके विभिन्न रूपों, राजवंशों की कुलदेवी, सौभाग्य देवी -लक्ष्मी, दुर्भाग्य देवी -ज्येष्ठा, चामुंडा व अन्य देवियों के विभिन्न स्वरूप देखे जा सकते हैं।

देव प्रतिमाओं में पुरानी सभ्यता की अद्भुत अभिव्यक्ति

इसकी देव प्रतिमा दीर्घा में भी 1,000 वर्ष से भी पुरानी सभ्यता प्रदर्शित है। इसमें शिव के द्वार रक्षक-वीर भद्र, स्थानक विष्णु, गदा शंख धारण किए हुए सूर्यदेव, क्षीर सागर में विश्राम करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार धन के देवता कुबेर व अन्य मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस आर्ट गैलरी की जैन प्रतिमा दीर्घा में भी करीब 1,000 वर्ष प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं। इनमें तीर्थंकर आदिनाथ, महावीर स्वामी, नेमीनाथ तथा अन्य जैन प्रतिमाएं विविध स्वरूपों में निहारी जा सकती हैं।

खोई हुई धरोहर की बहाली

जयपुर मेट्रो ने पुरातत्व की दृष्टि से उपयुक्त छोटी-बड़ी चौपड़ के 150 तथा 250 वर्ष पुराने जमीने में गड़े दो ऐतिहासिक जलकुंडों को बाहर निकाला है। शहरवासियों की खोई हुई इस धरोहर को बहाल करने के लिए इन अनावृत्त हुए खूबसूरत कुंडों को मेट्रो का कार्य पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करने का मेट्रो प्रशासन ने निर्णय किया। जयपुर के इतिहास की 18वीं शताब्दी की तस्वीरों व अभिलेखों से भी छोटी चौपड़ के बीचों बीच ऐतिहासिक कुंड की जानकारी सामने आई। सदियों पूर्व अटे ये बेमिसाल जलाशय कदाचित विश्व की दुर्लभ संरचनाओं में से एक हैं। इस बहाने मेट्रो परियोजना दल ने यहां एक बुनियादी ढांचा खोजा है, जो नगर की गुम हुई विरासत का खुलासा करती है। विश्व पर्यटन दिवस पर छोटी चौपड़ स्थित कुंड का पुनर्निर्माण कर सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इसको नया स्वरूप देने में मूल से प्राप्त पत्थरों एवं धौलपुर के सुंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया है।

इस अनिवर्चनीय नक्काशीदार कुंड के साथ ही 18वीं शताब्दी के मनोहारी फव्वारों, पानी निकलने वाले संगमरमर के गोमुखों को भी उनके मूल स्वरूप में संजोते हुए जयपुर मेट्रो की कला दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। भारत का प्रथम नियोजित शहर जयपुर जब अपनी स्थापना की तीसरी सदी मनाने की ओर अग्रसर है और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, तब यहां जयपुर मेट्रो रेल तथा इसकी कला दीर्घा का संस्थापन सोने पे सुहागा सा प्रतीत हो रहा है। इस आर्ट गैलरी ने निश्चय ही जयपुर मेट्रो एवं अशेष जयपुर शहर में एक सौंदर्य मूल्य जोड़ा है। •

राजस्थानी संस्कृति के सौंदर्य के वाहक

पणिहारी गीत, नृत्य और संवाद

महेश पारीक
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान अपने रेगिस्तान और सुनहरे रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। यहां पानी की कमी है और इस वजह से रेगिस्तानी इलाकों में अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पानी लाने के लिए महिलाओं को सिर पर मटके रख धोरों के आर-पार बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इन महिलाओं को पणिहारी कहा जाता है। सुनसान इलाकों में पानी की जरूरत की विकट परिस्थितियों के बीच भीषण गर्मी में तपती रेत और धूल भरी आंधियों के बीच सिर पर मटके से पानी लाना इन पणिहारियों के लिए बहुत मुश्किल और बोझिल काम है। पानी लाने की इन मुश्किल पद-यात्राओं की विकटता को कम करने के लिए पणिहारियों ने लोक गीतों के माधुर्य के साथ, नृत्य और रोचक संवाद के रूप में दिल-बहलाव के अनेक तौर-तरीके विकसित कर लिए। समय के साथ इन तौर-तरीकों ने राजस्थान की संस्कृति को इस कदर प्रभावित किया कि इससे जुड़ी संगीत, नृत्य, संवाद और तहजीब की एक समृद्ध परंपरा विकसित हो गई। आज पणिहारियों के संगीत, नृत्य और संवाद अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति के जरिये राजस्थान की संस्कृति के सौंदर्य को दूर-दूर तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों और पुलों से सटी वॉल आर्ट के जरिए सरकार भी ऐसी सांस्कृतिक अदाओं को लोकप्रिय बना रही है।

पणिहारी गीत

यह सर्वविदित है कि संगीत विविध संस्कृतियों को जोड़ने का शक्तिशाली साधन है। यह अपनी पौराणिक कहानियों, उत्कृष्ट सामग्री और जादुई अभिव्यक्ति के जरिये विभिन्न पलों को जीवंत कर सकता है। पारंपरिक पणिहारी गीत राजस्थान की हर महिला के जीवन को छूते हैं। पानी, बादल और बरसात के संदर्भ के साथ बहती लहरों और नदियों की सुरीली लय को व्यक्त करने वाले पारंपरिक पणिहारी गीत राजस्थान की लोक-संस्कृति के साथ महिलाओं के दस्तूर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये गीत महिलाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम उपलब्ध करवाते हैं और उनके जीवन को दर्शाते हैं। पणिहारी संगीत के पास श्रोताओं को देने के लिए बहुत कुछ है। संबंध, प्रेम, प्रतीक्षा और अप्रत्याशित भेंटों की सामंजस्यपूर्ण कहानियां आखिरी तक बांधे रखती हैं।

पणिहारी गीतों के लिए कोई औपचारिक या शास्त्रीय स्वर या राग तय नहीं हैं। वे मधुर धुनें हैं जो एक महिला के दिल से सहज रूप से निकलती हैं।

पणिहारी अपने बच्चों और पति के लिए आराम का त्याग करती हैं। उनका जीवन आधुनिक कामकाजी महिलाओं की जीवन शैली के समान है जो काम पर जाती हैं और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। इन गीतों के जरिये महिलाएं अपनी मुश्किलें साझा करती हैं और राहत महसूस करती हैं।

पणिहारी नृत्य

पणिहारी नृत्य राजस्थान का सह-युगल लोक नृत्य है जो प्रसिद्ध घूमर नृत्य की तरह ही होता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती हैं। यह एक तरह का समूह नृत्य है और अक्सर उत्सव या त्योहार पर किया जाता है।

पणिहारी संवाद

राजस्थान की बहुरंगी परंपराओं में अपने श्रोताओं को बताने के लिए कई कहानियां हैं, जो उन्हें भावनाओं, प्रेम और कर्तव्यपरायणता के मधुर संबंधों की शानदार सवारी कराती हैं। पणिहारियों के बीच आपसी वार्तालाप इन्हीं परंपराओं के प्रतिबिंब हैं। इन वार्तालापों में महिलाओं के रोजमर्रा के घरेलू कर्तव्यों, अनजाने बलिदानों और अपनी सास-ननद के साथ खट्टे-मीठे रिश्तों के अलावा मोहल्ले, गांव, रिश्तेदारी और आस-पड़ोस की ताजा खबरों का आदान-प्रदान शामिल है। इनमें शासन, समाज, अर्थ, कला, कथा-साहित्य और संस्कृति के कई ऐसे समृद्ध संवाद भी शामिल हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित होकर बहुत समृद्ध हो गए हैं।

ज्यादातर पणिहारियां पढ़ी-लिखी नहीं होतीं, लेकिन इनमें से कुछ का संवाद कौशल बहुत समृद्ध होता है। उनकी खबर की बारीकियों की समझ, अनेक स्तर के संवाद के साथ तथ्यों की जांच, ब्योरेवार याद रख पाने की क्षमता, अंदरखाने की खबरों को निकलवाने का कौशल और प्रभावशाली संवाद अदायगी एक कुशल संप्रेषक के गुणों की मिसाल पेश करते हैं।

लेकिन जिस तरह पणिहारी लोक गीतों को सहेजने के प्रयास हुए हैं वैसे प्रयास इन संवादों के अभिलेखन को लेकर नहीं हुए। मौजूदा प्रसार के माध्यम से इसमें उनकी रुचि जगाना जरूरी है। इससे हम न केवल पानी के महत्व बल्कि नारी के वात्सल्य और प्रेम के महत्व को भी समझेंगे। •

पन्नाधाय और अमराजी भगत पैनोरमा

टी.आर. कंडारा
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

चित्तौड़गढ़ में अमरा जी भगत और पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन दोनों पैनोरमा के निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लोकदेवता अमरा जी भगत (अनगढ़ बावजी) के पैनोरमा तथा चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत माताजी की पांडोली में पन्नाधाय पैनोरमा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दोनों पैनोरमा के निर्माण के लिए उन्होंने पहले ही 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पन्नाधाय पैनोरमा निर्माण के लिए राशि स्वीकृति के साथ ही चित्तौड़गढ़ यूआईटी द्वारा 7 बीघा जमीन आवंटित की गई है। जिला कलक्टर ने भदेसर तहसील की आक्या ग्राम पंचायत के नरबदिया में 3.50 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। पैनोरमा में अमरा जी भगत द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार के कार्यों को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। दोनों पैनोरमा में मुख्य पैनोरमा भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, छतरी, स्कल्पचर्स, ऑडियो-वीडियो सिस्टम, शिलालेख, विभिन्न आर्ट वर्क सहित अनेक कार्य होंगे।

पन्नाधाय का अविस्मरणीय बलिदान

विश्व इतिहास में पन्नाधाय के त्याग जैसा दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। अविस्मरणीय बलिदान, साहस, त्याग, स्वाभिमान एवं स्वामी भक्ति के लिए पन्ना का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। पन्ना राणा सांगा के पुत्र राणा उदयसिंह की धाय मां थी। पन्नाधाय स्वामी को सर्वस्व अर्पण करने के लिए राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई। पन्नाधाय को सर्वोत्कृष्ट बलिदान के लिए जाना जाता है जिन्होंने 1536 ईस्वी में अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बाल्यावस्था में ही बलिदान देकर मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदयसिंह की रक्षा की थी।

लोक देवता अमराजी भगत

जिले के भदेसर तहसील के नरबदिया गांव में लोक देवता अमराजी भगत का समाधि स्थल है। ऐसी मान्यता है कि जब अमरा भगत का जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म के 9 दिन तक अपनी मां का दूध नहीं पिया था। सूर्य पूजन की रस्म पूरी करने के बाद मां का दूध पीने पर इस यशस्वी बालक की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैली। उन्होंने प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए अनगढ़ बावजी की धूणी पर तपस्या की और लोगों को बचाने के प्रयास किए। •

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023

खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने की कवायद

नरेंद्र सिंह शेखावत
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

खेल प्रतिभाओं को तलाशने एवं तराशने के लिए 23 जून, 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2022 से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और अब राज्य सरकार-प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए शहरी ओलंपिक खेल आयोजित करा रही है। राजस्थान में किया जा रहा यह प्रयोग अपने आपमें ऐतिहासिक है। दुनिया में इतनी बड़ी जन भागीदारी का खेल आयोजन आज तक कहीं नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी यह प्रमाणित किया है। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तहत 7-7 खेलों का आयोजन होगा। ग्रामीण ओलंपिक के तहत कबड्डी, टेनिसबॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, शूटिंग बॉल, रस्साकशी का आयोजन होगा जबकि शहरी ओलंपिक के तहत कबड्डी, टेनिसबॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं 4 दिन, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 5 दिन, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 3 दिन एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 4 दिन आयोजित होंगी, वहीं शहरी ओलंपिक के तहत पालिका स्तरीय प्रतियोगिताएं 6 दिन, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 3 दिन एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 4 दिन आयोजित होंगी।

हर वर्ग कर रहा इस पहल का स्वागत

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से उत्साह का माहौल बना है। पिछले साल आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हर वर्ग ने हिस्सा लेकर पहल का स्वागत किया है। यह उत्साह प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। इन खेलों में जाति, धर्म व उम्र का कोई भेदभाव नहीं है। मैदान में हर आयु वर्ग के खिलाड़ी टीम भावना से खेलते हुए दमखम दिखा रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक में प्रदेश के बुजुर्गों का जोश देखने को मिला है। गत वर्ष एक से डेढ़ लाख ऐसे लोगों ने इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है। खेलों से भाईचारा, सद्भाव और आपसी समन्वय का माहौल बनता है। इसी सोच के साथ राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है।

फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का सपना होगा साकार

ग्रामीण और शहरी ओलंपिक आयोजन से फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का सपना साकार होगा। आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि आई है। इससे स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ-साथ युवा पीढ़ी नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगी, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। खेलों से युवाओं में आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति प्रबल होती है। साथ ही तत्काल निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता का भी विकास होता है।

छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का अहम प्रयास

इन खेलों के जरिये राज्य सरकार प्रदेश में खेलों का ऐसा माहौल बना रही है जिससे भविष्य में हमारी प्रतिभाएं देश-विदेश तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करेंगी। खेलों से प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। ये प्रतियोगिताएं राज्य के गांव ढाणी में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में एक बड़ा प्रयास साबित हुई हैं। राज्य में नई खेल संस्कृति विकसित करने तथा ग्रामीण और शहरी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की सोच के साथ ये खेल आरंभ किए गए हैं। इन खेलों के जरिये राज्य सरकार प्रदेश में खेलों का ऐसा माहौल बना रही है जिससे भविष्य में हमारी प्रतिभाएं देश-विदेश तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करेंगी। खेलों से प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। ये प्रतियोगिताएं राज्य के गांव-ढाणी में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में एक बड़ा प्रयास साबित हुई हैं। राज्य में नई खेल संस्कृति विकसित करने तथा ग्रामीण और शहरी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की सोच के साथ ये खेल आरंभ किए गए हैं।

खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार के प्रयास

राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सम्मान राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियां दी गई हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु बजट, जमीन आवंटन, अभ्यास हेतु आवश्यक उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध रूप से खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। •

हाथी भाटा

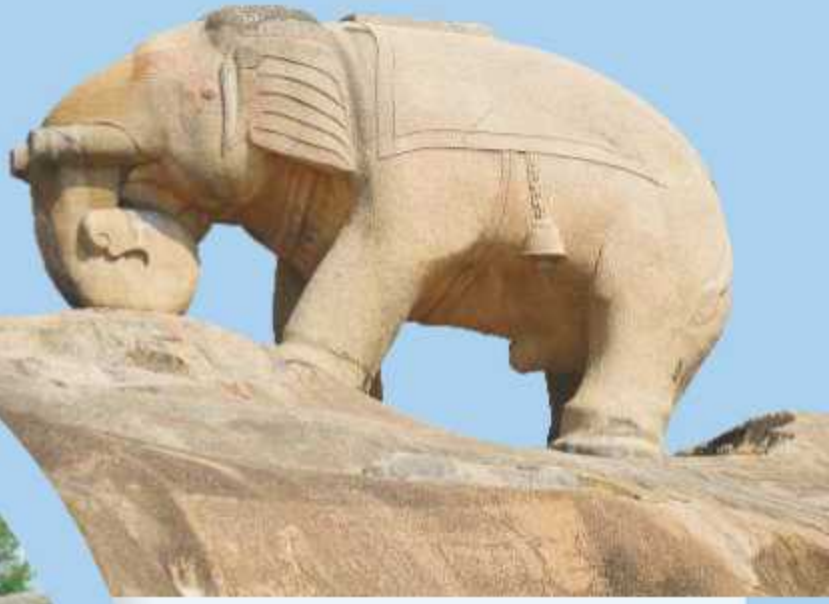

टोंक जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर उनियारा रोड पर ककोड़ गांव के समीप ऐतिहासिक हाथी भाटा स्थित है। दूर से ऐसा लगता है कि कोई सजीव हाथी खड़ा हो लेकिन यह पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी है। यहां पर एक प्राकृतिक बावड़ी भी है, जिसमें हमेशा पानी रहता है।

आलेख और छाया: लीला दिवाकर

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

तब

अब

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

@DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, बी-3, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 33.30 रुपये • 1,00,000 प्रतियां